राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस
क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 09 जुलाई 2026 वर्ष-9,अंक-157 पृष्ठ-06 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया, ईवीएम बनाने में भी भारत करेगा मदद

ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल

नई दिल्ली।

भारत-इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील पर मुहर लग गई है। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया इसे खरीदने वाला दूसरा देश बन गया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते हुए। इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) विकसित करने में मदद करेगा। इंडोनेशिया दौरे का दूसरे दिन मंगलवार सुबह पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उन्हें गले भी लगाया। पीएम मोदी दिन में इंडोनेशिया के मंदिर प्रम्बानन भी जाएंगे। 9वीं शताब्दी में बना यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल के प्रदर्शन के बाद इंडोनेशिया ने इसे खरीदने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट भी उपलब्ध कराएगा।

क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण में निवेश करेगा। भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग बंदरगाह का विकास करेंगे। यह बंदरगाह मलक्का जलडमरूमध्य पर स्थित है और भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से करीब 100 मील की दूरी पर है।

पहला कॉलम

शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी लश्कर का टॉप कमांडर जाकिर गनी ढेर

पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े आतंकी का चार दिन बाद मिला शव, हथियार और गोला-बारूद भी बरामद

जम्मू।

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर जाकिर गनी को मार गिराया है। अधिकारियों के अनुसार, शनिवार को शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ के चार दिन बाद घटनास्थल से उसका शव बरामद किया गया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जाकिर गनी पहलगाम आतंकी हमले से भी जुड़ा हुआ था और लंबे समय से सुरक्षा बलों की तलाश में था।वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान पहले गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी थीं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इलाके में तलाशी अभियान जारी रखा गया और मंगलवार को तलाशी के दौरान एक शव बरामद हुआ। मौके से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए हैं। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुष्टि हुई कि मारा गया आतंकी जाकिर गनी था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शोपियां जिला लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों का संवेदनशील क्षेत्र माना जाता रहा है। यह इलाका लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) जैसे संगठनों के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। दक्षिण कश्मीर को पीर पंजाल पर्वतमाला से जोड़ने वाला यह क्षेत्र घने सेब के बागानों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आतंकियों के लिए छिपने और आवाजाही का सुरक्षित मार्ग बनता रहा है।पिछले कुछ वर्षों में शोपियां में आतंकियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, बाहरी मजदूरों तथा सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं। इन घटनाओं को देखते हुए भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की विक्टर फोर्स सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस क्षेत्र में लगातार संयुक्त अभियान चला रही हैं। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि जाकिर गनी के मारे जाने से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है ताकि आतंकियों के किसी भी शेष नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके।

हिमाचल में अगले 7 दिन भीषण मॉनसून, भूस्खलन-बाढ़ का अलर्ट

शिमला।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने हिमाचल प्रदेश में अगले पांच से सात दिनों तक मॉनसून के अत्यधिक सक्रिय रहने का अनुमान जाहिर किया है। इस दौरान कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की संभावना है, इससे राज्य को भूस्खलन, अचानक बाढ़ (फ़्लैश फ़्लड) और नदियों व नालों के जलस्तर में वृद्धि जैसे गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है।

आईएमडी हिमाचल प्रदेश के मौसम केंद्र के प्रमुख ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य के करीब सभी ज़िलों में व्यापक बारिश दर्ज की गई, जिसमें मंडी और हमीरपुर जिलों के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हुई। उन्होंने पुष्टि की कि अगले पांच से सात दिनों के दौरान कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में मॉनसून सक्रिय रहेगा, जहाँ करीब हर दिन कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी ज़िलों में भी अगले चार से पांच दिनों तक मध्यम बारिश की उम्मीद है।मौसम केंद्र के प्रमुख ने चेतावनी दी कि लगातार भारी बारिश से भूस्खलन, अचानक बाढ़ आ सकती है और नदियों, नालों व अन्य जल निकायों में जल स्तर बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, कई जगहों पर दृश्यता कम हो सकती है और लगातार बारिश के कारण कृषि और बागवानी की फसलों को स्थानीय स्तर पर नुकसान पहुंच सकता है।

ई20 पेट्रोल पर केजरीवाल ने 29 वाहन कंपनियों से मांगा जवाब

नई दिल्ली।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ई20 पेट्रोल को लेकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर सात दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा है कि ई20 ईंधन का पुराने वाहनों के इंजन और माइलेज पर क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाता रहा है कि ई20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन और माइलेज पर विपरीत असर पड़ रहा है।

इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि यह भ्रामक जानकारी है और यदि ऐसा कोई दावा करता है तो वह सामने आए बताए कि किस वाहन में ई20 पेट्रोल ने नुक्सान हो रहा है। ऐसे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कंपनियों के सार्वजनिक बयान और ओनर्स मैनुअल में विरोधाभास है। केजरीवाल ने मांग की कि यदि ई20 से वाहनों को नुकसान होता है तो कंपनियां इसकी जिम्मेदारी लें।

अस्पतालों की लापरवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त करोड़ों की मेडिकल मशीनें खा रहीं धूल

नई दिल्ली ।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर महंगी मेडिकल मशीनें खरीदी गईं, लेकिन इनमें से कई मशीनें सालों से धूल खा रही हैं।

न मरीजों को इनका फायदा मिल रहा है और न ही इन पर खर्च हुए सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल हो पा रहा है। अब इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताते हुए दिल्ली सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों को ऐसी मशीनों की जांच कराने का आदेश दिया है,

जो खरीदी तो गईं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहीं।

अदालत के सामने दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की 15.42 करोड़ रुपये की पीईटी साइक्लोट्रॉन मशीन का मामला आया था, जो अप्रैल 2022 से बंद पड़ी है। इसके बाद कोर्ट ने सभी अस्पतालों में ऐसी मशीनों का ऑडिट कराने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट की विशेष पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी अस्पताल यह जांच करें कि कौन-कौन सी मशीनें खरीदी गईं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करना होगा।

राम मंदिर दान चोरीः तीन आरोपी पुलिस रिमांड पर, खुलेंगे कई राज

अयोध्या।

राम मंदिर में दान चोरी के मामले में पुलिस को तीन आरोपियों की कस्टडी रिमांड मिल गई है, जिससे इस प्रकरण से जुड़े कई नए राज खुलने की उम्मीद है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पाण्डेय नामक इन तीनों आरोपियों को मंगलवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत ने 40 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने अदालत से सात दिनों की रिमांड मांगी थी, यह दलील देते हुए कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं और उनसे मिली जानकारियों के आधार पर नए साक्ष्यों एवं अन्य वस्तुओं की बरामदगी आवश्यक है। पुलिस अब इन आरोपियों से रुपयों को कहां-कहां खपाया गया, कैसे चुराया गया और कहां छिपाया गया, इन सभी पहलुओं पर गहन पूछताछ करेगी।

यह मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट और निर्देशों के आधार पर ही दान चोरी के मामले में आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।

‘सेफ क्लिक 2.0’ अभियान डिजिटल सुरक्षा की ली गई शपथ

‘रन फॉर साइबर सेफ्टी’ में उमड़ा जनसैलाब

जबलपुर।

डिजिटल दौर में बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस के ‘सेफ क्लिक 2.0’ अभियान के तहत जबलपुर पुलिस ने बुधवार को ‘रन फॉर साइबर सेफ्टी’ मैराथन का आयोजन किया। पुलिस परेड ग्राउंड से शुरू हुई इस मैराथन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, युवा, खिलाड़ी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने साइबर सुरक्षा की शपथ दिलाकर किया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि ऑनलाइन लेन-देन करते समय सावधानी बरतें, अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी और निजी दस्तावेज किसी के साथ साझा न करें।

मैराथन पुलिस परेड ग्राउंड से शुरू होकर अंबेडकर चौक, हाईकोर्ट चौक, घंटाघर, तैयब अली चौक और पर्यटन तिराहा होते हुए वापस पुलिस परेड ग्राउंड पहुंची। इसमें करीब 600 से 700 नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने कहा कि ‘सेफ क्लिक 2.0’ अभियान के माध्यम से पुलिस लगातार लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, डिजिटल अरेस्ट, निवेश धोखाधड़ी, केवाईसी फ्रॉड और सोशल मीडिया हैकिंग जैसे अपराधों से बचने के उपाय बता रही है। पुलिस टीमें स्कूल, कॉलेज, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही हैं। मैराथन के समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मेडल एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी रही।

जबलपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज, लिंक, एपीके फाइल या अधिक लाभ वाले निवेश प्रस्ताव पर बिना जांच भरोसा न करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या सायबरक्राईम.जीओव्ही.इन पर शिकायत दर्ज कराएं।

मनरेगा का नया रूप वीबी जी राम जी कांग्रेस ने बताया अधिकारों का हनन और राज्यों पर बोझ

नई दिल्ली।

कांग्रेस ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह 1 जुलाई से लागू हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट (वीबी जी राम जी) को रोज़गार अधिकार की चोरी बताया है। कांग्रेस नेता और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि यह नई योजना अत्यधिक केंद्रीकृत है और इससे राज्य सरकारों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।कांग्रेस नेता रमेश ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू के लेख का हवाला देकर कहा कि नया कानून उस योजना की जगह ले रहा है, जो ग्रामीण परिवारों को काम का कानूनी अधिकार देती थी। उन्होंने लिखा कि वीबी जी राम जी असल में रोजगार के अधिकार की चोरी है। यह काम करने के संवैधानिक अधिकार की जगह एक ऐसी अत्यधिक केंद्रीकृत स्कीम ले आती है, जिससे राज्य सरकारों पर बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ पड़ता है। कांग्रेस नेता रमेश ने दावा किया कि नया कानून टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को सुविधा देने के बजाय उन्हें बाहर रखने के लिए करता है और यह मनरेगा की तरह पूरे साल उपलब्ध नहीं रहेगा।पूर्व वित्त मंत्री द्राबू ने अपने लेख में समझाया कि मनरेगा, जो एक अधिकार-आधारित और मांग-आधारित योजना थी और परिवारों को 100 दिनों के अकुशल काम का कानूनी अधिकार देती थी, उस अब एक फॉर्मूला-आधारित और केंद्र द्वारा तय करने वाले ट्रांसफर में बदल दिया गया है।कांग्रेस ने नए कानून के तहत मिलने वाली मज़दूरी को भी बिना किसी वाजिब वजह के बहुत कम बताया है।

पाकिस्तान में 17 पुलिसकर्मियों की हत्या सुरक्षा पर गंभीर सवाल

इस्लामाबाद।

भुखमरी और बदहाली से घिरे पाकिस्तान में हिंसा भी नहीं थम रही है। यहां अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर हिंसा और दहशत का माहौल है। जियारत जिले में बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने पुलिस बल को निशाना बनाते हुए एक बड़ा और घातक हमला किया है, जिसमें कम से कम 17 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। इस हमले ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हमले में कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि लगभग 15 पुलिसकर्मियों के लापता होने की खबर है। आशंका जताई जा रही है कि हमलावर उन्हें अपने साथ ले गए हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस बीच, बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने इस भीषण हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। संगठन ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसने मंगी डैम के पास स्थित पुलिस चौकी को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद उनके पैतृक गांवों और शहरों में अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है, जिससे परिवारों और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मारे गए पुलिसकर्मियों में दो थाना प्रभारी (एसएचओ) भी शामिल हैं, जो इस हमले की गंभीरता को दर्शाता है। यह हमला जियारत के मंगी डैम के पास स्थित एक पुलिस चौकी पर किया गया, जहाँ भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने अचानक धावा बोल दिया। हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सुरक्षा बलों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। सुरक्षा बलों ने तत्काल प्रभाव से पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है ताकि लापता पुलिसकर्मियों का पता लगाया जा सके और हमलावरों को खोजा जा सके। इस अभियान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। यह कोई पहली घटना नहीं है जब बीएलए ने बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया हो। पिछले लगभग एक महीने में, इस संगठन ने प्रांत में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। पुलिस चौकी पर इस हमले से ठीक पहले, बीएलए ने जियारत में ही दो सैन्य शिविरों पर हमला करने का दावा किया था। 27-28 जून को हुए उस हमले में भी कई सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, और संगठन ने दावा किया था कि उसने शिविरों पर कब्जा कर हथियार भी लूटे थे।

इसके अलावा, 3-4 जुलाई को ग्वादर के जिवानी में कोस्ट गार्ड कैंप पर एक आत्मघाती हमला किया गया था। बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने विस्फोटकों से भरे वाहन के जरिए कोस्ट गार्ड कैंप को निशाना बनाया था और दावा किया था कि इस हमले में 30 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए, हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इन लगातार हमलों ने बलूचिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया है और यह दिखाता है कि क्षेत्र में अलगाववादी संगठन अभी भी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बचपन की असुरक्षा और समाज की विफलता

(लेखक- कुमार कृष्णन)

- श्रीगंगानगर की घटना से उठते सवाल

राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक तेरह वर्षीय छात्रा के साथ कथित सामूहिक यौन उत्पीड़न का मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं है। यह उस सामाजिक संकट का संकेत है, जिसकी आहट वर्षों से सुनाई दे रही है, लेकिन जिसे हम हर नई घटना के बाद कुछ दिनों के आक्रोश में भुला देते हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार एक नाबालिग छात्रा को कई दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ गंभीर अपराध किए जाने के आरोप हैं। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। न्यायालय का अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुँचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर उस प्रश्न को हमारे सामने खड़ा कर दिया है, जिससे बचना अब संभव नहीं—क्या भारत अपने बच्चों, विशेषकर अपनी बेटियों, को सुरक्षित बचपन दे पा रहा है?

हर बार जब ऐसी कोई घटना सामने आती है, तो हमारा सार्वजनिक विमर्श लगभग एक जैसा होता है। राजनीतिक बयान आते हैं, सोशल मीडिया पर आक्रोश उमड़ता है, कठोर दंड की मांग उठती है और कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन अपराध सामान्य नहीं होते। वे समाज की गहराइयों में मौजूद उन विकृतियों का परिणाम होते हैं, जिन्हें हम लंबे समय तक अनदेखा करते रहते हैं। इसलिए श्रीगंगानगर की घटना को केवल पुलिस कार्रवाई या अदालत की प्रक्रिया तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। यह हमारे सामाजिक चरित्र, नैतिक शिक्षा, प्रशासनिक सतर्कता और लोकतांत्रिक संवेदनशीलता की सामूहिक परीक्षा है।

भारत में बाल यौन हिंसा का संकट नया नहीं है। पिछले डेढ़ दशक में ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग बढ़ी है। इसका एक कारण यह भी है कि बच्चों के यौन शोषण को लेकर समाज में पहले की तुलना में अधिक जागरूकता आई है और पॉक्सो कानून के लागू होने के बाद शिकायत दर्ज कराने का रास्ता अपेक्षाकृत स्पष्ट हुआ है। लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध आज भी भयावह स्तर पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े लगातार बताते हैं कि हर वर्ष हजारों बच्चे यौन हिंसा का शिकार होते हैं। इनमें अधिकांश पीड़ित बच्चियां होती हैं और बड़ी संख्या में उनकी आयु किशोरावस्था से भी कम होती है।

इन आंकड़ों का सबसे भयावह पक्ष यह नहीं कि अपराध बढ़ रहे हैं, बल्कि यह है कि अधिकांश मामलों में अपराधी कोई अजनबी नहीं होता। वह परिवार का परिचित, पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र या ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर बच्चा और उसका परिवार भरोसा करता है। यानी खतरा बाहर से कम और भीतर से अधिक है। यह तथ्य हमारी पारंपरिक सुरक्षा की समझ को बदल देता है। हम बच्चों को अनजान लोगों से सावधान रहना सिखाते हैं, लेकिन क्या उन्हें यह भी सिखाते हैं कि किसी परिचित द्वारा अनुचित व्यवहार होने पर वे बिना भय अपनी बात कह सकें?

समाजशास्त्री लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि किसी भी समाज में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं होती। वह उस सामाजिक सोच का परिणाम होती है जिसमें शक्ति, प्रभुत्व और स्त्री के प्रति असमान दृष्टि गहराई से मौजूद होती है। जब स्त्री को बराबरी के मनुष्य के बजाय नियंत्रण और उपभोग की वस्तु की तरह देखने वाली मानसिकता संस्कृति, भाषा, मनोरंजन और रोजमर्रा के व्यवहार में सामान्य होने लगती है, तब उसके सबसे भयावह रूप बच्चों के विरुद्ध अपराधों में दिखाई देते हैं। इसलिए केवल अपराधियों को राक्षस कह देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यह भी देखना होगा कि ऐसी मानसिकता पैदा कैसे होती है और समाज उसे रोकने में क्यों विफल रहता है।

भारतीय समाज का एक बड़ा विरोधाभास यही है कि एक ओर हम कन्या पूजन करते हैं, स्त्री को शक्ति का स्वरूप बताते हैं, दूसरी ओर बच्चियों के प्रति हिंसा की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। यह विरोधाभास केवल धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार का प्रश्न है। सम्मान का अर्थ केवल प्रतीकात्मक पूजा नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सुरक्षा, समानता और गरिमा सुनिश्चित करना है। यदि एक बच्ची अपने घर, स्कूल, पड़ोस या सार्वजनिक स्थानों पर भी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो हमारी सांस्कृतिक घोषणाएँ खोखली सिद्ध होती हैं।

श्रीगंगानगर की घटना ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है—क्या हमारे सार्वजनिक संस्थान बच्चों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त सतर्क हैं? यदि किसी नाबालिग को संदिग्ध परिस्थितियों में लगातार विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाता है, तो क्या कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो समय रहते संदेह व्यक्त करे? यह प्रश्न केवल पुलिस का नहीं है। होटल, परिवहन तंत्र, स्थानीय समुदाय, बाल संरक्षण तंत्र और नागरिक समाज—सभी की भूमिका की निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक है। किसी भी सभ्य समाज में बच्चों की सुरक्षा केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं होती; वह सामाजिक संस्कृति का हिस्सा होती है।

यही कारण है कि इस घटना को केवल एक क्राइम स्टोरी की तरह पढ़ना पर्याप्त नहीं होगा। इसे भारतीय समाज के बदलते चरित्र, संस्थागत जवाबदेही और लोकतांत्रिक संवेदनशीलता के व्यापक संदर्भ में समझना होगा। क्योंकि जब बचपन असुरक्षित होने लगे, तब संकट केवल कानून का नहीं रहता, वह राष्ट्र के भविष्य का संकट बन जाता है।

भारत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए वर्ष 2012 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) लागू किया। इस कानून ने पहली बार बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की स्पष्ट परिभाषा दी, उनकी पहचान गोपनीय रखने का प्रावधान किया और त्वरित न्याय का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके बाद समय-समय पर कानून को और कठोर बनाया गया। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल कठोर कानून बना देने से अपराध रुक जाते हैं?

वास्तविकता यह है कि कानून का प्रभाव उसकी कठोरता से नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन से तय होता है। देश में आज भी अनेक मामलों में जांच लंबी खिंच जाती है, फोरेंसिक रिपोर्ट आने में देरी होती है, गवाह मुकर जाते हैं, पीड़ित परिवार सामाजिक दबाव और आर्थिक कठिनाइयों से टूट जाता है तथा मुकदमे वर्षों तक अदालतों में लंबित रहते हैं। न्याय में देरी केवल पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होती, बल्कि अपराधियों के भीतर यह विश्वास भी पैदा करती है कि दंड से बच निकलने की संभावना बनी हुई है।

श्रीगंगानगर की घटना ने एक बार फिर यह प्रश्न उठाया है कि क्या हमारी संस्थाएं बच्चों की सुरक्षा के प्रति पर्याप्त संवेदनशील हैं। यदि कोई नाबालिग कई दिनों तक संदिग्ध परिस्थितियों में विभिन्न स्थानों पर रहती है, तो क्या किसी स्तर पर चेतावनी की घंटी नहीं बजनी चाहिए? होटल, परिवहन व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन और नागरिक समाज—सभी की अपनी-अपनी जिम्मेदारी है। विकसित देशों में होटल उद्योग और सार्वजनिक संस्थानों के कर्मचारियों को मानव तस्करी तथा बाल शोषण की पहचान के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत में भी ऐसी व्यवस्था को गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता है।

लेकिन इस पूरे विमर्श का सबसे कठिन पक्ष समाज के भीतर छिपा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और विभिन्न अध्ययनों से यह तथ्य सामने आता रहा है कि अधिकांश मामलों में अपराधी कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं होता। वह परिवार का सदस्य, रिश्तेदार, पड़ोसी, शिक्षक, मित्र या परिचित होता है। इसका अर्थ यह है कि बच्चों की सुरक्षा का संकट केवल सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं है; वह विश्वास के दायरे के भीतर भी मौजूद है। यह स्थिति परिवारों के सामने नई चुनौती खड़ी करती है।

भारतीय परिवारों में यौन शिक्षा को लेकर आज भी असहजता है। माता-पिता बच्चों से इस विषय पर खुलकर बात करने से बचते हैं। परिणाम यह होता है कि बच्चे अनुचित व्यवहार की पहचान ही नहीं कर पाते या पहचान लेने के बाद भी भय, शर्म और अपराधबोध के कारण अपनी बात किसी से नहीं कह पाते। यही मौन अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। विद्यालयों में गुड टच-बैड टच, व्यक्तिगत सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और सहायता मांगने की प्रक्रिया पर व्यवस्थित शिक्षा अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है।

डिजिटल युग ने इस संकट को और जटिल बना दिया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट ने ज्ञान के नए अवसर दिए हैं, लेकिन अश्लील सामग्री, ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर ब्लैकमेल और यौन शोषण के नए रास्ते भी खोले हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीक के दौर में बच्चों की सुरक्षा केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं रह गई है। अभिभावकों और शिक्षकों को डिजिटल दुनिया की चुनौतियों को समझना होगा। निगरानी और विश्वास के बीच संतुलन बनाना आज पहले से अधिक आवश्यक हो गया है।

समाज को भी अपने भीतर झांकना होगा। क्या हम बच्चों के प्रति सचमुच संवेदनशील हैं? क्या किसी बच्चे की असामान्य स्थिति देखकर हम हस्तक्षेप करते हैं, या यह सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि यह किसी और का मामला है? नागरिक जिम्मेदारी का अर्थ केवल मतदान करना या कर देना नहीं है। यदि समाज अपने सबसे कमजोर नागरिकों की रक्षा के प्रति सजग नहीं है, तो लोकतंत्र का नैतिक आधार भी कमजोर पड़ जाता है।

मीडिया की भूमिका पर भी गंभीर विचार की आवश्यकता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चों से जुड़े यौन अपराधों की रिपोर्टिंग में संवेदनशीलता सर्वोपरि होनी चाहिए। पीड़ित की पहचान की रक्षा, अपुष्ट सूचनाओं से बचाव और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान—ये केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि पत्रकारिता की नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं। दुर्भाग्य से कई बार प्रतिस्पर्धा और सनसनी के कारण इन मूल्यों की उपेक्षा होती है। इससे पीड़ित और उसके परिवार की पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि हर ऐसी घटना को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का माध्यम बना देना समस्या का समाधान नहीं है।

अपराधी का कोई धर्म, जाति या दल नहीं होता; उसका केवल अपराध होता है। बच्चों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए। यह विषय चुनावी बहस का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प का होना चाहिए।

संपादकीय

शर्मसार हैं हम

अब आए दिन देश के प्रिंट मीडिया से लेकर अन्य सूचना माध्यमों में यौन अपराधों की विचलित करने वाली घटनाएं सुर्खियों में रहती हैं। यौन लिप्साओं का यह विस्फोट विचलित करने वाला है। कोई निर्भया, किसी के साहस के बूते अपने साथ हुए अन्याय को उजागर कर देती है, वहीं देश की अनेक निर्भयाएं यौन हिंसा व क्रूरता के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में त्रास झेलने को अभिशप्त हो जाती हैं। हाल की दो घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारह वर्षीय बालिका को चार दिन बंधक बनाकर दो दर्जन लोगों द्वारा दुराचार किया गया। इस मामले में 18 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ गिरफ्तारियां बाकी हैं। दूसरी घटना पश्चिम बंगाल की है जहां बारुईपुर में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। शव परीक्षण में पाया गया कि उसके सिर व निजी अंगों पर गंभीर चोटें थी। इतना ही नहीं, दुराचार के बाद उसे बोरे मे बंद करके जिंदा ही तालाब में डुबो दिया गया। दोनों ही घटनाएं विचलित करने वाली हैं, लेकिन श्रीगंगानगर की घटना हर संवेदनशील इंसान को हिला देने वाली है। जनाक्रोश के चलते प्रशासन ने न केवल 18 लोगों को गिरफ्तार किया बल्कि उन होटलों को भी ध्वस्त किया गया जहां अलग-अलग जगहों में बच्ची को बंधक बनाकर देह व्यापार कराया गया। निस्संदेह, मोबाइल के बढ़ते हस्तक्षेप से परिवार संस्था की चूलें हिली नजर आती हैं। कथित सोशल मीडिया समाज में विद्रूपताओं को जन्म दे रहा है। श्रीगंगानगर की बारह वर्षीय लड़की शहर से सौ किमी दूर अपने एक इंस्टाग्राम फ्रेंड से मिलने जाती है, जो उससे वहां दुराचार करता है। वहां से देर रात शहर लौटने पर एक रिक्शेवाले के झांसे में आकर होटल पहुंचती है और फिर उसके साथ दुराचार का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। परिजनों के लापता किशोरी के तलाश में थाने पहुंचने के बाद पुलिस हरकत में आती हैं, फिर उसे मुक्त कराया जाता है। निस्संदेह, ये घटनाएं इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। इस राक्षसी कृत्य से उद्वेलित लोग श्रीगंगानगर की सड़कों पर उतर आए। क्षुब्ध लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर कानून के रखवालों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जनाक्रोश को देखते हुए 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह कि भारतीय समाज में हो रहे यौन लिप्साओं के विस्फोट की वजह क्या है? ये नैतिक पतन की पराकाष्ठा क्यों हो रही है? हवस के भूखे भेड़िए न उम्र देखते हैं, न किसी बेटी की बेबसी। उस किशोरी के साथ हुई बर्बरता के बारे में सोचकर भी रूह कांपती है। जो शायद ही जीवनभर इस त्रासदी से उबर पाये। कहीं न कहीं इंटरनेट व सोशल मीडिया पर यौन स्वच्छंदता की पश्चिम की आंधी हमारे समाज को पतित कर रही है। हमारे परंपरागत शुचिता के रिश्तों को तार-तार करके निरंकुश यौन व्यवहार को तार्किक बताने की साजिश रची जा रही है। हम बच्चों को रामराज के संस्कार देते हैं, जबकि समाज में दानवराज का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। बच्चों को भी त्याग-तपस्या से लालन-पालन करने वाले मां-बाप की बजाय आभासी दुनिया के छद्म मित्र रास आ रहे हैं। जिसके सम्मोहन में यह किशोरी घर से निकली और उसका पहला शिकार बनी। हवस के भेड़िये भी परिस्थितियों की मारी लड़कियों को ही अपने शिकंजे में लेते हैं। ऐसे में बेटियों को भी घर से निकलते वक्त समय की संवेदनशीलता और लोगों की विश्वसनीयता को परखना चाहिए। घर वालों से चोरी-छिपे अनजान लोगों पर यकीन करने की वजह से अकसर बेटियां अपराधियों की आसान शिकार बनती हैं।

मिलावट है भारत के सपनों पर विषनुमा दाग

(लेखक - - ललित गर्ग)

भारत आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बन चुका है। आधुनिक राजमार्ग, बुलेट ट्रेन, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रगति निश्चय ही गौरव का विषय हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा कलंक है, जो इस समस्त प्रगति के माथे पर काले धब्बे की तरह दिखाई देता है-मिलावट। यह केवल खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व में आई मिलावट का भी प्रतीक है। यह किसी भी सभ्य समाज के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है कि एक ओर चिकित्सक रोगियों को स्वास्थ्य लाभ के लिए दूध, घी, फल, पनीर और पौष्टिक आहार लेने की सलाह देते हैं, वहीं दूसरी ओर बाजार में वही दूध डिटर्जेंट और यूरिया से भरा मिलता है, घी में जानलेवा रसायन मिलते हैं, फलों को जहरीले रसायनों से पकाया जाता है और दवाइयों तक में नकलीपन प्रवेश कर चुका है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर स्वस्थ जीवन की आशा किससे की जाए? नये भारत, विकसित भारत एवं मजबूत भारत का सबसे बड़ा हो- मिलावट-मुक्त भारत।

यह विडंबना केवल उपभोक्ता की नहीं, पूरे राष्ट्र की है। जिस देश की संस्कृति 'अन्नं ब्रह्म' और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का संदेश देती हो, वहां भोजन ही यदि विष बन जाए तो इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है? हाल के ही दिनों में देश के विभिन्न भागों से मिलावट के अनेक भयावह मामले सामने आए हैं। कहीं हजारों लीटर नकली दूध पकड़ा जाता है, कहीं करोड़ों रुपये का नकली शहद, कहीं मिलावटी घी, मावा और मसाले बरामद होते हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि जीवन बचाने वाली दवाइयों में भी नकली और घटिया सामग्री का उपयोग पाया गया। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानवता के विरुद्ध अपराध है। जो व्यक्ति लाभ कमाने के लिए किसी बच्चे, गर्भवती महिला, वृद्ध या बीमार व्यक्ति के भोजन और दवा में जहर घोल देता है, वह केवल व्यापारी नहीं, समाज का अपराधी है। दरअसल, मिलावट का सबसे बड़ा कारण केवल आर्थिक लालच नहीं, बल्कि नैतिक पतन है। पहले समाज में यह भावना थी कि दूसरों को कष्ट देकर कभी सुख नहीं मिल सकता। लोग ईश्वर, धर्म और समाज की नैतिक मर्यादाओं से डरते थे। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। त्वरित धन अर्जित करने की अंधी दौड़ ने संवेदनाओं को कुचल दिया है। अब कुछ लोगों के लिए मुनाफा ही धर्म बन गया है, चाहे उसकी कीमत किसी की जान क्यों न हो। यह स्थिति केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास का भी प्रश्न है। मिलावटी खाद्य पदार्थ कैंसर, किडनी, लीवर, हृदय रोग, हार्मोन असंतुलन और बच्चों में कुपोषण जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी बोझ बढ़ता है, परिवार आर्थिक संकट में फंसते हैं और राष्ट्र की उत्पादक क्षमता प्रभावित होती है। दूसरी ओर, जब भारतीय खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारी विश्वसनीयता भी कमजोर होती है। विकसित भारत का सपना केवल ऊंची इमारतों और तेज आर्थिक विकास से पूरा नहीं होगा; उसके लिए स्वस्थ नागरिक और शुद्ध खाद्य व्यवस्था अनिवार्य है।

विडंबना यह भी है कि हमारे यहां कानून तो हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, निरीक्षण तंत्र और विभिन्न एजेंसियां मौजूद हैं, फिर भी मिलावट का कारोबार फल-फूल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार, निरीक्षण व्यवस्था की कमजोरी, मुकदमों में देरी और दंड का अभाव है। त्योहारों पर कुछ छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई करके प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है, जबकि बड़े नेटवर्क अक्सर बच निकलते हैं। जब तक दोषियों को त्वरित और कठोर दंड नहीं मिलेगा, तब तक यह विषैला कारोबार समाप्त नहीं होगा। आज आवश्यकता केवल कानूनों की नहीं, बल्कि कठोर राजनीतिक इच्छाशक्ति की है। हर जिले में आधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित हों। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉकचेन आधारित आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक हर स्तर पर निगरानी सुनिश्चित की जाए। नकली दवाइयों और मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएं, ताकि कुछ महीनों के भीतर दोषियों को सजा मिल सके। ऐसे अपराधों को सामान्य आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि 'जनस्वास्थ्य के विरुद्ध जघन्य अपराध' घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन केवल सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। समाज की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। उपभोक्ताओं को जागरूक बनना होगा। प्रमाणित उत्पादों का उपयोग, संदिग्ध वस्तुओं की शिकायत, स्थानीय स्तर पर जन-जागरण अभियान और विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा नैतिक शिक्षा का प्रसार अत्यंत आवश्यक है। यदि समाज मिलावट को केवल अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक बहिष्कार योग्य कृत्य मानने लगे, तो इस बुराई पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि नहीं होता। विकसित राष्ट्र वह है जहां नागरिक बिना भय के भोजन कर सकें, जहां दवा जीवन बचाए, जहां व्यापार विश्वास पर आधारित हो और जहां ईमानदारी आर्थिक सफलता का आधार बने। जापान, जर्मनी और अनेक विकसित देशों की सफलता का रहस्य केवल तकनीक नहीं, बल्कि गुणवत्ता और नैतिक अनुशासन भी है। भारत यदि विश्वगुरु बनने का स्वप्न देखता है, तो उसे सबसे पहले अपने बाजार को विश्वास का बाजार बनाना होगा। आज आवश्यकता एक नए राष्ट्रीय अभियान की है-'मिलावट-मुक्त भारत अभियान'। जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान ने जनभागीदारी से व्यापक परिवर्तन की शुरुआत की, उसी प्रकार मिलावट के विरुद्ध भी राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। यह केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनचेतना का अभियान बने। प्रत्येक नागरिक यह संकल्प ले कि वह न मिलावट करेगा, न मिलावट को बढ़ावा देगा और न ही मिलावट करने वालों को सामाजिक सम्मान देगा।

विवेक ही धर्म है

युग के आदि में मनुष्य भी जंगली था। जब से मनुष्य ने विकास करना शुरू किया, उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई। आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से समस्या ने जन्म लिया।समस्या सामने आई तब समाधान की बात सोची गई। समाधान के स्तर दो थे- पदार्थ-जगत, मनो-जगत. प्रथम स्तर पर पदाथरे के सुनियोजित उत्पादन और उनकी व्यवस्था को आकार मिला। दूसरा स्तर मानसिक था। इस जगत की समस्याएं थी अपरिमार्जित वृत्तियां, असंतुलन और तनाव।

इन समस्याओं को समाहित करने के लिए धर्म की खोज हुई। धर्म का अर्थ है पारंपरिक मूल्य-मानकों से परे हटकर मनुष्य को सत्य की दिशा में अग्रसर करना। जब तक धर्म अपने इस परिवेश में रहता है, तब तक वह रूढ़ नहीं हो सकता। पर उद्देश्य की विस्मृति के साथ ही उसमें रूढ़ता आ जाती ह। रूढ़ धर्म को व्यक्ति अपने जीवंत संदभरे से काटकर परलोक के साथ जोड़ देता है। बस यहीं से धर्म में विकृति का प्रवेश होने लगता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि धर्म का संबंध हमारी हर सांस से होना चाहिए। ऐसा वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जो अपने जीवन की सतह पर दौड़-धूप कर रहे हैं। या फिर यह उन लोगों का काम है जो जीवन की गहराइयों में उतरकर अध्यात्म के प्रति समर्पित हो जाते हैं।

जीवन की सतह पर जीने वाले व्यक्ति धर्म की गहराई में नहीं उतर सकते, किंतु अध्यात्म के प्रयोक्ता की दृष्टि से वह गहराई छिपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति उतनी गहराई में उतरे, उन्हें धर्म की विकृतियों का बोध हुआ। जो धर्म मन को समाधान देने वाला था, वह स्वयं समस्या बनकर उभर गया। इस दृष्टि से उसमें संशोधन व परिवर्तन की अपेक्षा अनुभव हुई। अणुव्रत उसी आवश्यकता का आविष्कार है। यदि धर्म एक समस्या बनकर सामने नहीं आता तो उसे अणुव्रत के रूप में प्रस्तुति देने का कोई अर्थ ही नहीं था। अणुव्रत धर्म के साथ विवेक की अपरिहार्यता पर बल देता है। आगम की भाषा में विवेक ही धर्म है।

विचार मंथन

मध्य प्रदेश की जीवन दायनी

लेखक- सनत जैन

नर्मदा मध्य प्रदेश के लिए केवल एक नदी नहीं है। यह मध्य प्रदेश की जीवन दायनी नदी है। करोड़ों लोगों की आस्था और जीवन-यापन का माध्यम है। 87 फीसदी नदी मध्य प्रदेश में बहती है। सरदार सरोवर परियोजना के लिए सबसे ज्यादा जमीन मध्य प्रदेश की लगी। सबसे ज्यादा मुआवजा मध्य प्रदेश को देना पड़ा। सबसे बड़ा त्याग भी मध्य प्रदेश ने किया। हजारों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि, सैकड़ों गांव, जंगल और लाखों लोगों का जीवन इस परियोजना के कारण प्रभावित हुआ। किसानो की रोजी-रोटी छिन गई। लाखों लोगों का व्यवसाय चला गया। इसके बावजूद मध्य प्रदेश को इस समझौते में अपने 7,669 करोड़ रुपये के दावे से हाथ धोना पडा, उलटे गुजरात को 550 करोड़ रुपये देने पड़ रहे हैँ। जैसे लड़की की शादी में दहेज दिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति समझौते में मध्य प्रदेश की हुई है। आज जब मध्य प्रदेश पर भारी कर्ज है, ऐसे समय पर मध्य प्रदेश के लिए यह बड़ी वित्तीय आपदा भी है। यह समझौता न्याय, संघीय संतुलन और राज्यों के अधिकारों का प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। तीन दशक से अधिक समय से चल रहे इस विवाद का समाधान जिस तरह से हुआ है, वह स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। यह समझौता गुजरात के लिए ऐतिहासिक हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए यह एक आपदा है। इतिहास समझौते से नहीं बल्कि न्याय से बनता है। सबसे अधिक नुकसान उठाने वाले राज्य का शोषण किया जाए। ऐसे समझौते पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

सरदार सरोवर परियोजना मे लगभग 55 प्रतिशत डूब क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। हजारों किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई। सेकड़ों गांव उजड़े, पुनर्वास पर मध्य प्रदेश सरकार का भारी खर्च हुआ। कई दशकों तक आंदोलन चलते रहे। मध्य प्रदेश ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और बढ़ी हुई लागत के आधार पर 7,669 करोड़ रुपये का दावा गुजरात सरकार पर किया था। गुजरात इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है। कच्छ जैसे सूखे क्षेत्रों तक नर्मदा का पानी पहुंचा। गुजरात में सिंचाई, उद्योग, पेयजल और शहरी विकास के हर क्षेत्र में गुजरात को अभूतपूर्व लाभ मिला। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, आधुनिक गुजरात के विकास में नर्मदा नदी और सरदार सरोवर परियोजना की निर्णायक भूमिका है। मध्य प्रदेश के इस योगदान का गुजरात के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी ख्याल रखना था। विडंबना यह है, जिस मध्य प्रदेश ने सरदार सरोवर बांध के निर्माण की सबसे अधिक कीमत चुकाई। इसके कारण नर्मदा नदी के बरगी बांध का काम कई दशकों तक पिछड़ा रहा। आज भी बरगी बांध की नहरें नहीं बन पाई हैं। मध्य प्रदेश आज भी अपने हिस्से के पानी का उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण सरदार सरोवर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, मुआवजे पर भारी खर्च, हजारों आंदोलन होने से राज्य की आर्थिक स्थिति एवं अन्य सिंचाई योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाई। बरगी बांध से जुड़ी नहर परियोजनाएं कई वर्षों पीछे चली गईं हैं। इनकी लागत कई गुना बढ़ गई है। इस समझौते में इस सब का ध्यान नहीं रखा गया है। परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश का विशाल कृषि क्षेत्र अपने वैधानिक जल अधिकारों का लाभ भविष्य में भी नही ले पाएगा। इस समझौते के बाद गंभीर प्रश्न यह है, क्या वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों ने इस समझौते को प्रभावित किया है? जब केंद्र और चारों राज्यों में एक ही राजनीतिक दल की सरकारें हों, केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में समझौता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के होते हुए जब यह अपेक्षा स्वाभाविक हो। सभी राज्यों के साथ न्याय किया जाएगा। ऐसी स्थिति में समझौते के बाद जो स्थिति सामने आ रही है उसमें गुजरात को ही सारे लाभ मिले हैं। अन्य राज्यों के हितों की अनदेखी हुई है। मध्य प्रदेश की जनता यह पूछने का अधिकार रखती है। उसके हितों की पैरवी किसने की? मध्य प्रदेश सरकार ने इस फैसले को क्यों स्वीकार किया? क्या राज्य के आर्थिक और संवैधानिक अधिकारों पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष दृढ़ता से रखा है?

नर्मदा परियोजना राष्ट्रीय हित की योजना थी। नर्मदा नदी के जल का लाभ पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात का विकास भी देश का विकास है। विकास का अर्थ यह नहीं हो सकता, कमजोर राज्य के ऊपर ज्यादा बोझ डाल दें। जिस राज्य को ज्यादा फायदा मिला है, वह समृद्धि का प्रतीक बन जाए। संघीय व्यवस्था की मूल भावना यही है कि लाभ और बोझ दोनों का न्याय संगत बंटवारा समझौते में होना था, जो नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में इस समझौते की तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। आवश्यकता है, मध्य प्रदेश के आर्थिक प्रभाव का निष्पक्ष पुनर्मूल्यांकन हो। मध्य प्रदेश ने भूमि, पुनर्वास और योजना को पूर्ण करने में सबसे ज्यादा आर्थिक लागत लगाया है।

उसकी भरपाई भी मध्य प्रदेश को न्यायपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए। नर्मदा का पानी राष्ट्रीय संपदा है। समझौते का न्यायपूर्ण समाधान ही इस विवाद का वास्तविक अंत कर सकता है। इस समझौते का यही संदेश जा रहा है। जिस नर्मदा से गुजरात का भाग्य बदला, उसी नर्मदा के कारण गुजरात ने मध्य प्रदेश के साथ अन्याय किया है। मां नर्मदा इसको किस रूप में स्वीकार करेंगी, इसका आकलन भविष्य में ही हो सकता है।

अब एफपीआई फीस का भुगतान अमेरिकी डॉलर नहीं भारतीय रुपए में होगा

-यह बदलाव विदेशी पोर्टफोलियो और विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों पर लागू होगा

नई दिल्ली।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) नियमों में बदलाव करते हुए शुल्क भुगतान की व्यवस्था को अमेरिकी डॉलर की जगह भारतीय रुपए में कर दिया है। यह बदलाव विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों दोनों पर लागू होगा। नए नियम छह महीने बाद प्रभावी होंगे, ताकि विदेशी निवेशकों को नई व्यवस्था अपनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अधिसूचना के मुताबिक एफपीआई नियमों में 1,000 अमेरिकी डॉलर की जगह अब 90,000 रुपए शुल्क तय किया गया है। सेबी ने कैटेगरी-1 एफपीआई और एफवीसीआई के रजिस्ट्रेशन शुल्क को 2,500 डॉलर से बदलकर 2.3 लाख रुपए कर दिया है। इसी तरह देरी से भुगतान और कंटिन्यूएंस फीस में भी संशोधन किया है। भारत में एफपीआई के लेनदेन संभालने वाले डिजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को रजिस्ट्रेशन मिलने के पांच कार्य दिवस के अंदर यह शुल्क सेबी को जमा कराना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कम्प्लायंस और ऑपरेशंस को आसान बनाने के लिए एफपीआई रजिस्ट्रेशन के कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म में अब जन्म तिथि या कंपनी के गठन की तिथि भी शामिल की जाएगी। इसका मकसद मार्च में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी नई अधिसूचना के बाद पेन आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाना है। सेबी को वित्त वर्ष 2025-26 में एफपीआई और एफवीसीआई से रजिस्ट्रेशन, कंटिन्यूएंस और अन्य शुल्क के रूप में 1.298 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। इस राशि में जीएसटी भी शामिल है। सेबी ने कहा कि डॉलर में शुल्क लेने के कारण मैनुअल अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग और रियल-टाइम अकाउंटिंग में दिक्कतें आती थीं। इससे वित्तीय रिपोर्टिंग में भी देरी होती थी। नई व्यवस्था से इन समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी। सेबी ने कस्टोडियन द्वारा दिए जाने वाले शुल्क की व्यवस्था भी बदल दी है। अब उन्हें सालाना 10 लाख रुपए की जगह हर महीने 85,000 रुपए शुल्क देना होगा। सेबी ने म्युचुअल फंड नियमों में इंट्रा-डे उधारी से जुड़े बदलावों को भी अधिसूचित किया है। नए नियमों के तहत म्युचुअल फंड अब पे-इन और पे-आउट सेटलमेंट के समय के अंतर, एसेट क्लास के भीतर लेनदेन, फॉरेक्स सेटलमेंट और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए इंट्रा-डे उधार ले सकेंगे। यह सुविधा पहले से उपलब्ध उस व्यवस्था के अतिरिक्त होगी, जिसके तहत म्युचुअल फंड योजनाएं यूनिटधारकों को भुगतान के लिए अपनी नेट एसेट्स के 20फीसदी तक कर्ज ले सकती हैं। सेबी ने साफ कहा है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को दिन खत्म होने से पहले यह उधार चुकाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता, तो उसे म्युचुअल फंड नियमों के मुताबिक ओवरनाइट उधारी माना जाएगा।

मोबाइल रिचार्ज में भारी बढ़ोतरी तय, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

रिचार्ज प्लान 12 से 15 प्रतिशत तक मंहगे हो सकते

मुंबई।

भारतीय मोबाइल उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। जल्द ही आपके मासिक या वार्षिक रिचार्ज प्लान 12 से 15 प्रतिशत तक महंगे हो सकते हैं, जिससे आपकी जेब पर सीधा बोझ पड़ेगा। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (एआरपीयू) में सुधार लाने और 5जी नेटवर्क पर किए बड़े निवेश की भरपाई की तैयारी में हैं। पिछले टैरिफ बढ़ोतरी के झटके से उपभोक्ता अभी उबर भी नहीं सके थे कि यह दूसरी बड़ी वृद्धि सामने आने वाली है।टेलीकॉम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले तीन से चार महीनों के भीतर यह बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बाजार में अब केवल 3+1 खिलाड़ी होने के कारण, कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ाना आसान हो गया है और प्रतिस्पर्धा का दबाव कम हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाली तिमाही में सभी निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों के एआरपीयू में 1-1.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसका मुख्य कारण ग्राहकों का 2जी से 4जी और 5जी नेटवर्क पर अपग्रेड होना, पोस्टपेड ग्राहकों की बढ़ती संख्या और डेटा उपयोग में लगातार वृद्धि है।रिलायंस जियो और भारती एयरटेल अपने सब्सक्राइबर मार्केट शेयर में लगातार इजाफा कर रही हैं, जबकि दोनों ही कंपनियाँ देश के 90 प्रतिशत से अधिक जिलों में 5जी सेवाएं शुरू कर चुकी हैं और अपने नेटवर्क में अधिक 5जी डिवाइस जोड़ने पर काम कर रही हैं। वोडाफोन आइडिया भी लगभग 100 शहरों में अपनी 5जी सेवा का विस्तार कर रहा है। डेटा के बढ़ते इस्तेमाल को देखकर टेलीकॉम कंपनियों को लगता है कि कीमतों में बढ़ोतरी का सही समय है।

होर्मुज में फिर तनाव से कच्चे तेल में लगी आग, दुनियाभर के शेयर बाजारों में हड़कंप

–क्रूड ऑयल अचानक 3 फीसदी से ज्यादा की तेजी लेकर 76 डॉलर के पार पहुंचा

नई दिल्ली।

अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता बैठकों को लेकर आ रहे अपडेट्स के बीच दुनिया की 20 फीसदी तेल जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी होर्मुज स्ट्रेट फिर से तनाव की वजह बनता जा रहा है। वजह है अमेरिका का ईरान पर हमला। इन सबके बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में अचानक कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल मच गई है और दुनियाभर के शेयर बाजारों में भी हड़कंप मचा है, जो भारतीय शेयर बाजार के लिए निगेटिव संकेत दे रहे हैं। भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए प्रमुख संकेतक माना जाने वाला गिफ्ट निफ्टी भी रेड जोन में ट्रेड कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर गहराने लगा है। हॉर्मुज में तीन कॉमर्शियल जहाजों पर ईरान से मिसाइल अटैक के बाद अमेरिकी सेना ने पलटवार किया और ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयरस्ट्राइक की है। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार चल रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये जबरदस्त हमले उन लोगों को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुद्री रूट में आम नागरिकों वाले कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाकर अटैक किया है। एक बयान में कहा गया कि ये ताजा स्ट्राइक ईरान द्वारा उन तीन कमर्शियल जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में हैं, जो होर्मुज से गुज़र रहे थे और ये सीजफायर का सीधा उल्लंघन था। ईरानी हमलों पर अमेरिकी स्ट्राइक के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक फिर से उछाल आ गया।

बैंकों के लोन में तेजी और मुनाफा भी बढ़ने की उम्मीद, जमा की रफ्तार धीमी

-कवरेज वाले बैंकों का कुल शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर बढ़ सकता है 5 फीसदी

नई दिल्ली।

बैंकों का लोन तेजी से बढ़ रहा है और मुनाफा भी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ जमा की रफ्तार अभी भी लोन के मुकाबले धीमी है। इसके अलावा ब्याज से होने वाली कमाई पर भी दबाव बना रह सकता है। खासकर प्राइवेट बैंकों में मार्जिन थोड़ा घटने की आशंका है। सरकारी बैंकों में भी कुछ दबाव रहेगा, हालांकि उनकी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रह सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून तिमाही में उसके कवरेज वाले बैंकों का कुल शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर करीब 5फीसदी बढ़ सकता है। हालांकि पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें 8फीसदी की गिरावट आने का अनुमान है।रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट बैंकों का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 11फीसदी बढ़ सकता है। वहीं सरकारी बैंकों का मुनाफा करीब 2फीसदी घटने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इसमें एक बड़ा कारण बैंक ऑफ बड़ौदा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई से जुड़े एक कानूनी मामले के निपटारे के लिए बैंक को करीब 5,700 करोड़ रुपए का एकमुश्त प्रावधान करना पड़ सकता है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को अलग कर दें, तो बाकी सरकारी बैंकों का मुनाफा भी करीब 12फीसदी बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जून तिमाही में बैंकों की लोन ग्रोथ मजबूत बनी रही। 15 जून तक आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में लोन 17.7फीसदी की दर से बढ़े, जबकि डिपॉजिट सिर्फ 12फीसदी बढ़े यानी बैंक तेजी से कर्ज दे रहे हैं, लेकिन उसी रफ्तार से उनके पास जमा नहीं बढ़ रही है।

चालू माह में मिल रही अल्ट्रोज और टियागो पर विशेष छूट

नई दिल्ली ।

जुलाई महीने में टाटा मोटर्स ने अपनी लोकप्रिय हैचबैक अल्ट्रोज और टियागो पर आकर्षक छूट की घोषणा की है। अल्ट्रोज के रेसर वैरिएंट पर सबसे अधिक 55,000 रुपये तक का डिस्काउंट उपलब्ध है। इसके पेट्रोल और डीज़ल वैरिएंट्स पर 15,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस मिल रहा है।

वहीं, अल्ट्रोज सीएनजी मॉडल पर इन छूटों के साथ 20,000 रुपये का इंटरवेंशन ऑफर भी दिया जा रहा है। अल्ट्रोज की एक्स-शोरूम कीमतें 6.3 लाख रुपये से 10.65 लाख रुपये के बीच हैं, और यह कई इंजन विकल्पों व उन्नत सुरक्षा फीचर्स जैसे 6 एयरबैग और ईएससी के साथ आती है।

दूसरी ओर, टाटा मोटर्स प्री-फेसलिफ्ट टियागो के बचे हुए स्टॉक पर 35,000 रुपये तक की छूट दे रही है। एक्सई वैरिएंट को छोड़कर, टियागो के पेट्रोल और सीएनजी दोनों मॉडल्स पर 15,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस और 5,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।

शेयर बाजार भारी गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 1,677, निफ्टी 516 अंक गिरा

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ सप्ताह के तीसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट अमेरिका के ईरान पर किये हमलों के बाद दुनिया भर के बाजारों में मची उथल-पुथल से बिकवाली हावी होने और कच्चे तेल की कीमतें फिर बढ़ने से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स सेंसेक्स 1,677.12 टूटकर 76,503.60 पर खिसक गया जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 516.65 अंक की गिरावट के साथ ही 23,882.05 पर फिसल गया। इसके अलावा व्यापक बाजारों में, निफ्टी मिडकैप इंडेक्स और स्मॉलकैप इंडेक्स में में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। वहीं क्षेत्रवार देखें तो सभी प्रमुख सूचकांक गिरावट पर हुए। निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। पीएसयू बैंकों के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट आई, इसके अलावा निफ्टी बैंक , निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी एफएमसीजी) और निफ्टी मीडिया में भी गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही निफ्टी ऑयल एंड गैस , निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा,निफ्टी और निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गिरावट रही।

निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में जियो फाइनेंशियल, इंटरग्लोब एविएशन, श्रीराम फाइनेंस, मारुति सुजुकी और एचयूएल शामिल रहे, जबकि ओएनजीसी और बजाज ऑटो, हिंडाल्को और कोल इंडिया के शेयर उछले।

इस बिकवाली में बीएसई-सूचीबद्ध शेयरों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में 8 लाख करोड़ से ज्यादा की गिरावट आई। गत दिवस बीएसई-सूचीबद्ध शेयरों का बाजार मूल्यांकन 480.20 लाख करोड़ रुपए था, जो अब घटकर 471.44 करोड़ रुपए हो गया है। इस प्रकार एक ही दिन में निवेशकों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। गौरतलब है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान के साथ युद्धविराम समाप्त हो गया है जिसके बाद से ही निवेशकों ने बाजार से दूरी बना ली है।

वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार की कमजोर शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 625 अंक फिसलकर 77,555.52 के निचले स्तर तक खुला जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 50 गिरकर 24,207.20 के स्तर तक रहा।

तीन महीनों में खत्म होगी 53 कंपनियों के प्री-लिस्टिंग शेयरधारक लॉक-इन

–जिन शेयरों के लॉक–इन खत्म हो रहे हैं, उनकी वैल्यू 11 अरब डॉलर

नई दिल्ली।

नुवामा इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज के विश्लेषण के मुताबिक जुलाई से सितंबर के बीच कुल 53 कंपनियों के प्री-लिस्टिंग शेयरधारक लॉक-इन हटाए जाने हैं, जिन शेयरों के लॉक-इन खत्म हो रहे हैं, उनकी वैल्यू 11 अरब डॉलर है। हालांकि ये सभी शेयर, बाजार में नहीं आएंगे क्योंकि प्रवर्तक और प्रवर्तक समूहों के पास भी इनका एक बड़ा हिस्सा है। कुछ शेयरों के लिए एक महीने का लॉक-इन खत्म हो रहा है और कुछ अन्य के लिए तीन या छह महीने का लॉक-इन खत्म होने वाला है, जिन शेयरों का एक महीने का लॉक-इन खत्म हो रहा है, उनमें सीएमआर ग्रीन टेक्नॉलजीज, टर्टलमिंट फिनटेक सॉल्यूशंस, वॉटरवेज लीजर टूरिज्म, हेक्सागन न्यूट्रिशन, एडवाइट ज्वेल्स और सीएसएम टेक्नॉलजीज शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी शेयरों का तीन महीने का लॉक-इन सितंबर तक खत्म हो जाएगा। इनके अलावा, ओम पावर ट्रांसमिशन और ऑनईएमआई टेक्नॉलजी सॉल्यूशंस ऐसी कंपनियां हैं, जिनका तीन महीने का लॉक-इन पीरियड सितंबर के आखिर से पहले खत्म हो जाएगा। भारत कोकिंग कोल, शैडोफैक्स टेक्नॉलजीज और आय फाइनैंस उन फर्मों में शामिल हैं, जिनका छह महीने का लॉक-इन खत्म होने वाला है।

जानकारों का कहना है कि आईपीओ लॉक-इन की समयसीमा खत्म होने से द्वितीयक बाजार में शेयरों की संख्या में तेजी नहीं आती है क्योंकि संस्थागत निवेशकों और प्राइवेट इक्विटी फंड आम तौर पर खुले बाजार में सीधे शेयर बेचने के बजाय बातचीत के जरिये नियोजन या ब्लॉक ट्रेड के जरिये अपना निवेश निकालने की योजना बनाते हैं। स्वतंत्र इक्विटी विश्लेषक ने कहा कि अक्सर लेनदेन खास तरीके से तय या नियोजित किए जाते हैं। ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर और खुद कंपनी भी इच्छुक खरीदारों को खोजने में मदद करते हैं ताकि ज्यादा उथल-पुथल के बिना शेयर बिक जाएं।

सोने और चांदी के भावों में आई नरमी

नई दिल्ली ।

सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को नरमी आई है। कीमती धातुओं में ये गिरावट डॉलर में मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जून बैठक के मिनट्स जारी होने से पहले निवेशकों की सतर्कता से आई है। इससे सोने-चांदी की कीमतें गिरी हैं। दुनिया भर के साथ ही घरेलू बाजारों में भी कीमतें नीचे आयी हैं। आज कॉमेक्स पर सोना 4,100 डॉलर प्रति औंस से नीचे आया। वहीं चांदी भी 60 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक खिसकी। घरेलू मार्केट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी फिसला है। एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव 1,44,950 रुपये, जबकि चांदी के भाव 2,29,300 रुपये के करीब रहे। आज सोने के वायदा भाव की शुरुआत में भी कमी आई। एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क अगस्त अनुबंध 192 रुपये की गिरावट के साथ ही 1,45,200 रुपये के भाव पर खुला जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,45,392 रुपये था। सोने के वायदा भाव इस साल 1,80,779 रुपये के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचे थे। दूसरी ओर चांदी के वायदा भाव की शुरुआत कमजोर रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 842 रुपये की गिरावट के साथ 2,30,015 रुपये पर खुला। पिछला बंद भाव 2,30,857 रुपये था। चांदी का वायदा भाव इस साल 4,20,048 रुपये किलो के भाव पर सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा।

सरकार ने ईवी वाहन में लगे सॉफ्टवेयर एवं उपकरणों का ऑडिट के दिए निर्देश

–यह कदम इलेक्ट्रिक वाहन हैकिंग की चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया

नई दिल्ली।

सरकार ने वाहन विनिर्माताओं और वाहन कलपुर्जा बनाने वाली कंपनियों को कनेक्टेड कारों और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में लगे वाहन प्रबंधन सॉफ्टवेयर एवं उपकरणों का व्यापक ऑडिट करने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने बताया कि यह निर्देश यात्री और वाणिज्यिक दोनों वाहन श्रेणियों पर लागू होगा।

यह कदम इलेक्ट्रिक वाहन हैकिंग की चिंताओं के मद्देनजर ऐपल और गूगल को तीन ऐप हटाने का निर्देश दिए जाने के बाद उठाया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने वाहन विनिर्माताओं के संगठन सायम और वाहन कलपुर्जा विनिर्माताओं के संगठन एक्मा को लिखे पत्र में कंपनियों से अपने बैटरी संचार इंटरफेस का ऑडिट करने और असुरक्षित डिफॉल्ट सेटिंग, कमजोर प्रमाणीकरण या असुरक्षित ओवर-द-एयर विकल्पों को खत्म करने का आग्रह किया है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड ने भी इस पत्र को देखा है। उसके मुताबिक भारी उद्योग मंत्रालय ने यह भी कहा कि वाहन विनिर्माताओं को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ मिलकर कारखाना स्तर पर बेहतर और दमदार साइबर सुरक्षा डिजाइन प्रोटोकॉल स्थापित करने चाहिए। पत्र में हैकिंग की घटनाओं को सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता बताया है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरुरत है। सूत्र ने बताया कि सरकार की मुख्य चिंता कनेक्टेड कारों के लिए है।

अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल

-ईरान ने हमलों को समझौते का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी

नई दिल्ली।

होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिका ने मंगलवार को ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए और साथ ही ईरान को अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने की दी गई अस्थायी छूट वापस ले ली है।

इन घटनाओं ने पिछले महीने दोनों देशों के बीच हुए युद्धविराम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि यह कार्रवाई युद्धविराम के उल्लंघन और समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने इन कदमों को समझौते का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है।मीडिया रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी गई है कि हमलों में ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी प्रणाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर कहा कि ईरान की आक्रामक कार्रवाई न केवल अनुचित और खतरनाक थी, बल्कि यह युद्धविराम का स्पष्ट उल्लंघन भी थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी शहर सीरिक, क़ेश्म द्वीप और बंदर अब्बास में कई विस्फोट हुए। एक व्यावसायिक बंदरगाह पर प्रोजेक्टाइल गिरने से कुछ लोग घायल हुए, जबकि मछली पकड़ने वाली कई नौकाओं में आग लग गई। हालांकि, किसी नागरिक की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका ने ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्यात की जो अस्थायी अनुमति दी थी उसे भी रद्द कर दिया है।

कल्ट फिट ने आईपीओ के लिए सेबी के पास जमा किए दस्तावेज, 950 करोड़ जुटाने की तैयारी

नई दिल्ली।

फिटनेस और वेलनेस कंपनी कल्ट फिट ने आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी के पास कागजात जमा कर दिए हैं। इस आईपीओ से कंपनी 950 करोड़ रुपए तक की नई पूंजी जुटा सकती है। कंपनी भारत में हेल्थ और वेलनेस सेवाओं की बढ़ती मांग का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। इस ऑफर में नए शेयर जारी करना और मौजूदा निवेशकों की बिक्री पेशकश शामिल है। मामले के जानकार लोगों का मानना है कि आईपीओ का कुल आकार करीब 4,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। टेमासेक, फिटनेस फर्स्ट लक्जमबर्ग, चिराटे वेंचर्स, टाटा डिजिटल, एक्सेल इंडिया, कलारी कैपिटल और श्रोडर्स कैपिटल जैसे मौजूदा निवेशक ओएफएस में करीब 17.86 करोड़ शेयर बेचने की योजना बना रहे हैं। हर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए है। इस आईपीओ में सह-संस्थापक मुकेश बंसल, एंजेल निवेशक ब्रूनो रैशल और अभिनेता ऋतिक रोशन भी अपने शेयर बेच रहे हैं। शेयर बेचने वालों में एशियन पेंट्स की प्रमोटर कंपनी डोली ट्रेडिंग ऐंड इन्वेस्टमेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंपनी सन एन सैंड होटल्स, एंडिया पार्टनर्स के संस्थापक सतीश अंद्रा, मिंत्रा के पूर्व सीईओ अनंत नारायणन का फैमिली ट्रस्ट और अभिनेता ऋतिक रोशन की निवेश कंपनी एक्सट्रीम ब्रांड्स भी शामिल हैं। कल्ट डॉट फिट में मैकरिची इन्वेस्टमेंट्स सबसे बड़ी शेयरधारक है, जिसके पास 20.3 फीसदी हिस्सेदारी है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और अपने कल्ट एलीट और कल्ट नियो फिटनेस सेंटरों को बढ़ाने के लिए करेगी। वह नए कल्टस्पोर्ट रिटेल आउटलेटों में भी निवेश करेगी, लीज से जुड़े पेमेंट करेगी, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन पर खर्च बढ़ाएगी और सामान्य कॉरपोरेट कार्यों में इसका इस्तेमाल करेगी। 31 मार्च 2026 तक कल्ट फिट भारत का सबसे बड़ा फिटनेस और ऐक्टिव-लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म था। इसके 77 शहरों में 708 फिटनेस सेंटर थे। 2025-26 में कंपनी के करीब 9,87,000 फिटनेस सदस्य थे जो पैसे देकर सेवाएं लेते हैं।

फैब्रिक्स कंपनी कुसुमगर का 650 करोड़ रुपए का खुला आईपीओ

-आईपीओ खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में इसके शेयरों की मांग मजबूत

नई दिल्ली।

इंजीनियर्ड फैब्रिक्स बनाने वाली कंपनी कुसुमगर का बहुप्रतीक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफर बुधवार 8 जुलाई से निवेशकों के लिए खुल गया है। कंपनी इस सार्वजनिक निर्गम के जरिए 650 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। हालांकि, यह पूरा इश्यू ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) है, इसलिए इस आईपीओ से मिलने वाली रकम कंपनी के पास नहीं जाएगी, बल्कि प्रमोटर शेयरधारकों को मिलेगी। आईपीओ खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में इसके शेयरों की मजबूत मांग है। ऐसे में कई निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या इस आईपीओ में निवेश करना सही रहेगा या नहीं।

रिपोर्ट के मुताबिक कुसुमगर का आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल पर आधारित है। इसके तहत प्रमोटर करीब 1.55 करोड़ इक्विटी शेयर बेच रहे हैं। कंपनी इस इश्यू के जरिए कोई नए शेयर जारी नहीं कर रही है। आईपीओ का प्राइस बैंड 398 रुपए से 419 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। एक लॉट में 35 शेयर शामिल हैं यानी खुदरा निवेशकों को कम से कम 14,665 का निवेश करना होगा। वहीं अधिकतम 13 लॉट के लिए करीब 1,90,645 का निवेश करना पड़ेगा।

आईपीओ खुलने से पहले कुसुमगर के अनलिस्टेड शेयर ग्रे मार्केट में मजबूत प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। बाजार सूत्रों के मुताबिक शेयर करीब 590 के भाव पर ट्रेड कर रहे हैं। यह आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड 419 रुपए के मुकाबले 171 रुपए प्रति शेयर या करीब 40.81 फीसदी का ग्रे मार्केट प्रीमियम दर्शाता है। हालांकि, निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल बाजार की धारणा को दर्शाता है। इसे लिस्टिंग या भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं माना जा सकता।कुसुमगर आईपीओ में निवेश करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई है। शेयरों का आवंटन 13 जुलाई को हो सकता है। सफल निवेशकों के डिमैट खाते में शेयर 14 जुलाई तक पहुंच सकते हैं। वहीं, कंपनी के शेयरों की 15 जुलाई को शेयर बाजार में लिस्टिंग होने की उम्मीद है। चूंकि यह पूरा इश्यू ऑफर फॉर सेल है, इसलिए आईपीओ से जुटाई गई राशि कंपनी के कारोबार में इस्तेमाल नहीं होगी। कंपनी ने अपने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में स्पष्ट किया है कि इश्यू से मिलने वाली पूरी रकम संबंधित प्रमोटर शेयरधारकों को जाएगी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पेरिस एफसी ने पूर्व चेल्सी कोच लियाम रोसेन्योर को हेड कोच नियुक्त किया

पेरिस। पूर्व चेल्सी हेड कोच लियाम रोसेन्योर को पेरिस एफसी ने अपनी पुरुष टीम का नया मैनेजर नियुक्त किया है। कुछ महीनों पहले प्रीमियर लीग ने उन्हें पद से हटाया था, जिसके बाद इंग्लिश कोच को यह जिम्मेदारी मिली है। लीग 1 की इस टीम ने मंगलवार को पुष्टि की है कि 41 वर्षीय रोसेन्योर ने जून 2028 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वे आधिकारिक तौर पर 9 जुलाई से काम शुरू करेंगे, जब टीम प्री-सीजन ट्रेनिंग के लिए लौटेगी। रोसेन्योर, एंटोनी कोम्बोउरे की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले सीजन में क्लब को 11वें स्थान पर पहुंचाने से पहले लीग 1 में बने रहने में मदद की थी। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद, क्लब ने कोम्बोउरे के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि वह एक नया अध्याय शुरू करना चाहता है। अप्रैल में चेल्सी में अपने छोटे से कार्यकाल के खत्म होने के बाद रोसेन्योर फुटबॉल मैनेजमेंट में वापसी कर रहे हैं। पूर्व डिफेंडर स्टैमफोर्ड ब्रिज पर चार महीने से भी कम समय तक रहे और फिर क्लब से अलग हो गए।

पेरिस एफसी ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को तैयार करने और फुटबॉल का एक महत्वाकांक्षी, आक्रामक शैली अपनाने के लिए रोसेन्योर की ख्याति ने उन्हें क्लब को अगले चरण में ले जाने के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाया। क्लब ने एक बयान में कहा, '41 वर्षीय लियाम रोसेन्योर के पास पहले से ही उच्चतम स्तर का काफी अनुभव है। युवा प्रतिभाओं को निखारने की क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले लियाम रोसेन्योर, पेरिस एफसी की विचारधारा और स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए एकदम सही हैं। महत्वाकांक्षी, आकर्षक और आक्रामक फुटबॉल के प्रति उनका नजरिया क्लब की भविष्य की महत्वाकांक्षाओं से मेल खाता है।' पेरिस एफसी के स्पोर्टिंग डायरेक्टर मार्को नेपे ने इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए रोसेन्योर को एक आधुनिक कोच बताया जो खिलाड़ियों और टीम दोनों को विकसित करने में सक्षम हैं। नेपे ने कहा, 'लियाम रोसेन्योर में वे सभी गुण हैं जिनकी हमें तलाश थी।

जिम्बाब्वे दौरे और एशियन गेम्स में गौतम गंभीर नहीं होंगे भारत के कोच

वीवीएस लक्ष्मण संभालेंगे जिम्मेदारी

नई दिल्ली। भारतीय टीम को इंग्लैंड दौरे के बाद जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। इस दौरे के लिए सोमवार (6 जुलाई) को श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम का ऐलान हुआ है। इसके बाद भारतीय टीम को एशियन गेम्स में खेलने है। खबर है कि जिम्बाब्वे दौरे और एशियन गेम्स में भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर नहीं होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई के लॉग रिकॉर्ड के अनुसार जुलाई के अंत में जिम्बाब्वे दौरे और सितंबर में एशियन गेम्स के लिए कोचिंग स्टाफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से होगा। वीवीएस लक्ष्मण के सपोर्ट

स्टाफ की अगुआई करने की उम्मीद है। सीओई में उनके साथी कोच सुनील जोशी और ऋषिकेश कानिटकर के भी उनके साथ जुड़ने की संभावना है।

एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज सीरीज में टकराव

यह व्यवस्था खास तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि जापान के नागोया में होने वाले एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की घरेलू सीरीज में टकराव होना है। इससे पहले सितंबर के बीच में भारत में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज होगी। इत्तेफाक से अफगानिस्तान उस सीरीज का मेजबान होगा। जिम्बाब्वे दौरे के योजना के मुताबिक, भारतीय टीम के कुछ सदस्य 19 जुलाई को हरारे पहुंचेंगे।

जिम्बाब्वे में 3 मैचों की सीरीज– बाकी खिलाड़ी 19 जुलाई को लॉर्ड्स में तीसरे और आखिरी वनडे के बाद 20 जुलाई को टीम से जुड़ेंगे। टीम 20 से 22 जुलाई तक और फिर 24 जुलाई को आराम करेगी और ट्रेनिंग करेगी।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की हार जारी

● इंग्लैंड ने टीम इंडिया को किया 76 पर ढेर

नई दिल्ली। इंग्लैंड ने भारत को 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच मैच में 125 रनों से हरा दिया और 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। नॉटिंघम के ट्रेंटब्रिज में मंगलवार (7 जुलाई) को भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। फिल सॉल्ट ने अर्धशतक जड़ा। भारत के लिए प्रिंस यादव ने अच्छी गेंदबाजी की। 2 विकेट झटके। इसके जवाब में भारत 11.4 ओवर में 76 रन पर ढेर हो गया।

इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने जबरदस्त गेंदबाजी की। जोफ्रा आर्चर (3 ओवर में 3/29) और जोश टंग (4 ओवर में 4/28) ने पावरप्ले में जबरदस्त आक्रामकता के साथ गेंदबाजी की। जब भारत का स्कोर पांच ओवर में 5 विकेट पर 52 रन हो गया, तभी मैच का नतीजा लगभग तय हो गया था।

सबसे बुरी बात यह रही कि यह हाल के समय में भारत के सबसे खराब बल्लेबाजी प्रदर्शनों में से एक था, जिसमें खराब शॉट चयन और लड़ने का जज्बा न होना साफ दिखा। बाकी का समय बस औपचारिकता भर था। पावरप्ले के दौरान शिवम दुबे से पहले नंबर 7 पर हर्षित राणा जैसे 'हिट-एंड-मिस' वाले खिलाड़ी को भेजने पर कई लोगों ने हैरानी भी जताई।

वैभव सूर्यवंशी ने फिर दो छक्के लगाए (एक जोफ्रा आर्चर और एक जोश टंग की गेंद पर) लेकिन उनकी 13 रन की पारी सिर्फ पांच गेंदों में खत्म हो गई। उनके दाहिने कंधे पर आए एक तेज बाउंसर पर उन्होंने हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे जोस बटलर के दस्तानों में चली गई। इससे वैभव सूर्यवंशी को यह अहसास हो गया कि इंटरनेशनल क्रिकेट हमेशा बच्चों का खेल नहीं होता।

अभिषेक शर्मा डीप एक्स्ट्रा कवर पर कैच आउट हो गए। यह वही इलाका है जहां वह पहले भी कई बार आउट हो चुके हैं। इशान किशन ने हुक करके एक छक्का तो लगाया, लेकिन जल्द ही आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर फ्लिक करने की कोशिश की और स्क्वायर के पीछे खड़े फील्डर के हाथों में गेंद मार बैठे। अक्षर पटेल को शॉर्ट बॉल की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फुलर लेंथ मिली और उसका किनारा लगकर गेंद स्टंप्स के पीछे चली गई।

भारत की सबसे बड़ी हार

दूसरे सबसे कम स्कोर पर आउट

पावरप्ले में पहली बार गंवाए 5 विकेट

नई दिल्ली। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम का हार का सिलसिला जारी है। इंग्लैंड ने 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में मंगलावर (7 जुलाई) को 125 रनों से हरा दिया। यह भारतीय टीम की सबसे बड़ी हार है। वह टी20 इंटरनेशनल में पहली बार 100 से ज्यादा रन से हारी। टॉस हारकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम 11.4 ओवर में 76 रन पर आउट हो गई। यह भारत का सबसे न्यूनतम स्कोर है। भारतीय टीम ने पावरप्ले में 5 विकेट गंवा दिए। छठे ओवर में ही हर्षित राणा बल्लेबाजी के लिए आ गए। पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय टीम ने पावरप्ले में 5 विकेट गंवाए। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 5 मैचों से जीत का इंतजार है। उसने 4 मैच गंवाए हैं और 1 मैच बेनतीजा रहा है। भारत ने जीत के लिए कभी इतना लंबा इंतजार नहीं किया।

भारतीय टीम का हार का सिलसिला जारी

- 125 रन से इंग्लैंड ने हराया, ट्रेंटब्रिज, 2026
- 80 रन से न्यूजीलैंड ने हराया, वेलिंगटन, 2019
- 76 रन से साउथ अफ्रीका ने हराया, अहमदाबाद, 2026
- 51 रन से साउथ अफ्रीका ने हराया, मुल्लनपुर, 2025
- 50 रन से न्यूजीलैंड ने हराया, विशाखापत्तनम, 2026

(ऊपर दिए गए पांच में से चार दिसंबर 2025 के बाद आए हैं)

0–2 से पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना की शानदार वापसी

11 मिनट में पलटी बाजी, मेसी बने संकटमोचक

नई दिल्ली। लियोनेल मेसी ने एक बार फिर अर्जेंटीना के लिये 'संकटमोचक' की भूमिका निभाई और मिस्र के खिलाफ 79वें मिनट तक 2 गोल से पिछड़ रही मौजूदा चैम्पियन टीम को 3-2 से जीत के साथ विश्व कप क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया। निर्धारित समय में 11 मिनट बाकी रहने तक अर्जेंटीना दो गोल से पिछड़ रहा था और ऐसा लगने लगा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद मेसी की फुटबॉल के महासमर से विदाई का समय आ गया है। इसके बाद अर्जेंटीना ने चमत्कारिक वापसी करते हुए तीन गोल दागकर जीत दर्ज की और दुनिया भर में उसके करोड़ों प्रशंसकों ने भी राहत की सांस ली। इसमें से बराबरी का गोल 83वें मिनट में छठा विश्व कप खेल रहे मेसी ने दागा था जिनके अब विश्व कप कैरियर में 21 गोल हो गए हैं। अब अर्जेंटीना का सामना शनिवार (11 जुलाई) को कंसास सिटी में स्विटजरलैंड या कोलंबिया से होगा।

मेसी अपने आंसू नहीं रोक सके

आखिरी सीटी बजने के बाद मेसी अपने आंसू नहीं रोक सके। उन्होंने 83वें मिनट में इस विश्व कप में आठवां गोल करके टीम को 2-2 से बराबरी पर पहुंचाया। विजयी गोल स्टॉपेज टाइम में एंजो फर्नांडिस ने दागा। वहीं क्रिस्टियन रोमेरो ने 79वें मिनट में अर्जेंटीना के लिये पहला गोल किया था।

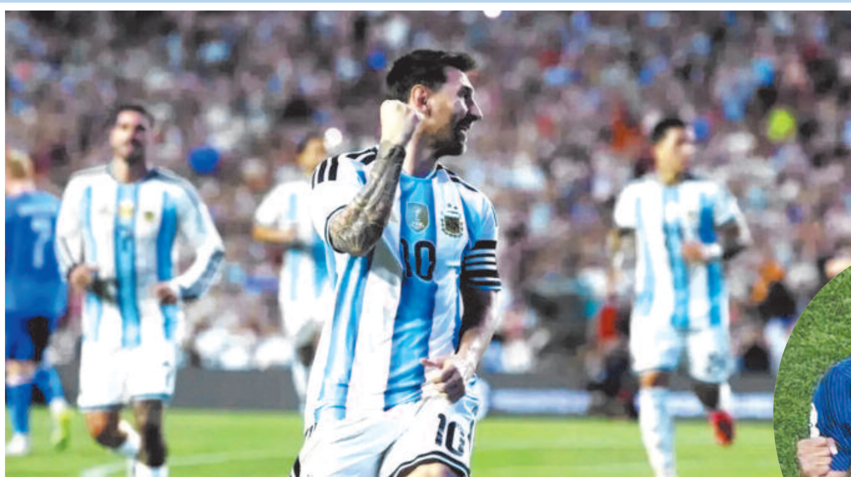

मेसी पेनल्टी को गोल में नहीं बदल पाए

मिस्र ने यासिर इब्राहिम और मुस्तफा जिको के गोल के दम पर 2-0 से बढ़त बना ली थी। मेसी को पहले हाफ में मौका मिला था, लेकिन उनकी पेनल्टी किक को मिस्र के गोलकीपर मुस्तफा शोबीर ने बचा लिया था। फिर जब स्कोर 1-0 था, तब उनका शॉट गोलपोस्ट से टकरा गया। अर्जेंटीना की नजरें लगातार दूसरी बार खिताब जीतने वाली ब्राजील (1958 और 1962) के बाद पहली टीम बनने पर है।

15वें मिनट में मिस्र ने बढ़त बना ली– मैच से पहले अर्जेंटीना को प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन 15वें मिनट में मिस्र ने बढ़त बना ली जब लिसांद्रो मार्तिनेज को चकमा देकर इब्राहिम ने मारवान आतिया के क्रॉस पर गोल दाग दिया। अर्जेंटीना को तुरंत पेनल्टी स्पॉट के साथ बराबरी का मौका मिला, लेकिन मेसी के शॉट को शोबीर ने बायीं ओर डाइव लगाकर बचा लिया।

एम्बाप्पे के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी की जांच शुरू

पराग्वे के सांसद ने परवरिश का उड़ाया मजाक

नई दिल्ली। विश्व कप में फ्रांस के हाथों पराग्वे की हार के बाद पराग्वे के एक सांसद द्वारा कीलियन एम्बाप्पे के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार किये जाने के मामले में फ्रांस के अभियोजकों ने गंभीर सार्वजनिक अपमान और नफरत या हिंसा भड़काने के आरोपों में जांच शुरू कर दी है। फ्रांस के अभियोजकों के कार्यालय ने मंगलवार (7 जून) को बताया कि आनलाइन घृणा से निपटने वाली राष्ट्रीय ईकाई को फ्रेंच फुटबॉल महासंघ से शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की गई है। पराग्वे की लिबरल रेडिकल पार्टी की सीनेटर सेलेस्टी अमारिला ने एक्स पर नस्लीय टिप्पणी की थी। इससे पहले एम्बाप्पे के गोल के दम पर फ्रांस ने पराग्वे को हराया था। अमारिला ने फ्रांस के कप्तान के मूल, परवरिश, शिक्षा और चेहरे मोहरे का मजाक बनाया था। फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है जहां उसका सामना मोरक्को से होगा। एम्बाप्पे ने उन्हें 'घिनौनी महिला' करार देते हुए कहा था कि वह पराग्वे की कांग्रेस में सेवा के लायक नहीं हैं।

अमारिला ने पत्र जारी किया

बाद में अमारिला ने सोशल मीडिया पर एम्बाप्पे के लिए फ्रेंच और स्पेनिश भाषा में एक खुला पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि उनकी समस्या खिलाड़ी से थी, न कि फ्रांस देश से।

अभिषेक नंबर 1

वैभव टॉप-10 से बाहर

भारत-इंग्लैंड तीसरे टी20 के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-15 खिलाड़ी

नई दिल्ली। भारत-इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत को बेशक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रन के लिहाज से सबसे बड़ी हार मिली हो, बेशक इस मैच में भारतीय बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से लड़खड़ा गई हो, लेकिन इस मुकाबले के बाद अगर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बल्लेबाजों की बात करें तो अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर हैं।

वहीं इस टी20 सीरीज के दूसरे मैच में डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी टॉप-10 से बाहर हैं।

भारत-इंग्लैंड तीसरे टी20 मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने 3 मैचों में एक अर्धशतक की मदद से 112 रन बनाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर हैं जिन्होंने 3 मैचों में एक अर्धशतक के साथ अब तक कुल 110 रन बनाए हैं। इंग्लैंड के बैटर जैकब बेथेल इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 3 मैचों में एक अर्धशतक के साथ 89 रन बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में टॉप-10 से बाहर हैं। वैभव ने 2 मैचों में 27 रन बनाकर 12वें नंबर पर हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: देश का मान बढ़ाने टीम इंडिया ग्लास्गो रवाना

नई दिल्ली। भारत फिर दुनिया के सबसे बड़े खेल मंचों में से एक पर अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। देश के खिलाड़ी अब स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में तिरंगे का मान बढ़ाने उतरेंगे। इस मौके पर भारतीय ओलंपिक संघ ने मंगलवार सात जुलाई 2026 को खिलाड़ियों और अधिकारियों के दल को भव्य विदाई दी। साथ ही उन आधिकारिक सेरेमोनियल और प्रतियोगिता किट का भी अनावरण किया, जिसे भारतीय खिलाड़ी ग्लास्गो में पहनेंगे। इस समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरन और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद रहे। खिलाड़ियों, कोचों, सहयोगी स्टाफ और अन्य पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, ''हमारे खिलाड़ी नए भारत की खेल प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। मैं सभी खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि वे बिना किसी डर के खेलें, खेल भावना का सम्मान करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें।''

खिलाड़ियों की भव्य विदाई, नई किट भी लॉन्च

23 जुलाई से होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में मनसुख मांडविया ने कहा, ''ग्लास्गो में हमारे सर्वश्रेष्ठ खेलों में से दस नहीं है, लेकिन खेल तो खेल है। हमें यकीन है कि हमारे खिलाड़ी पूरे उत्साह से खेलेंगे और देश को गौरवान्वित करके विश्व खेल जगत में भारत की छवि और मजबूत करेंगे।'' कार्यक्रम में खेल सचिव हरि रंजन राव, भारतीय दल के चीफ-डि-मिशन रोहित राजपाल और डिप्टी चीफ-डि-मिशन रवि बंगानी भी मौजूद रहे। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, ''आज भारतीय खेलों के लिए एक नए गौरवशाली अध्याय की शुरुआत है। भारत की जर्सी पहनने वाले हर खिलाड़ी ने वर्षों की मेहनत, अनुशासन और त्याग के दम पर यह मौका हासिल किया है।

खेलों में मेजबान के तौर पर बढ़ रही भारत की साख: मनसुख मांडविया

इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वैश्विक खेल समुदाय में भारत के बढ़ते कद की बानगी इससे मिलती है कि भारत में होने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत ने पिछले कुछ अर्से में कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी की है, जिसमें विश्व चैंपियनशिप भी शामिल है।

मनुसख मांडविया ने कहा, ''खेल आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। एक समय वह भी था जब महासंघ विश्व और अंतरराष्ट्रीय महासंघों से भारत में एशियाई खेल, एशियाई चैंपियनशिपस, विश्व चैंपियनशिप के आयोजन के लिए कहते थे लेकिन उन्हें भारत के सामर्थ्य पर संदेह रहता था।''

संक्षिप्त समाचार

26 साल की सबसे बड़ी कटौती, सऊदी अरब ने सस्ता किया कच्चा तेल

रियाद , एजेंसी। सऊदी अरब ने अगस्त के लिए कच्चे तेल की कीमत में 26 साल की सबसे बड़ी कटौती कर दी है। इससे वैश्विक तेल बाजार में हलचल तेज हो गई है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह राहत की खबर मानी जा रही है। लेकिन आखिर सऊदी अरब ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्या इससे पेट्रोल-डीजल सस्ता होगा और महंगाई पर कितना असर पड़ेगा? दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में शामिल सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमत में 26 वर्षों की सबसे बड़ी कटौती कर वैश्विक ऊर्जा बाजार को चौंका दिया है। अगस्त के लिए अरब लाइट क्रूड की कीमत में 11 डॉलर प्रति बैरल की कमी की गई है। इससे पहले जुलाई के लिए भी 6 डॉलर प्रति बैरल की कटौती की गई थी। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से सामान्य होने के बाद तेल की आपूर्ति बढ़ गई है और बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा भारत जैसे देशों को मिल सकता है, जो अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करते हैं।

चीन में भूस्खलन से 33 लोग दबे : 17 को बचाया गया, 16 की तलाश जारी

बीजिंग, एजेंसी। चीन के पश्चिमी गांसू प्रांत के पहाड़ी इलाके में मंगलवार को हुए भूस्खलन में 33 लोग मलबे में दब गए। सरकारी मीडिया के मुताबिक, अब तक 17 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 16 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सभी प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द बचाने के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच, सेंट्रल चीन के हुबेई प्रांत में सोमवार रात आए तेज तूफान और आंधी-बारिश से कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 275 लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति अब भी लापता है। मौसम विभाग के मुताबिक, कई इलाकों में 149 किमी/घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलीं। अगले 24 घंटे में 260 मिमी तक बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। चीन के मौसम विभाग ने सुपर टाइफून 'बावी' को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। यह तूफान 290 किमी/घंटा तक की रफ्तार वाली हवाओं के साथ प्रशांत महासागर से ताइवान की ओर बढ़ रहा है। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है।

ढाका के पास नेशनल सिटिजन पार्टी' की रैली में जोरदार बम धमाका

ढाका, एजेंसी। पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक बार फिर हिंसा और अशांति की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी ढाका के नजदीकी इलाके सावर में सोमवार को एक राजनीतिक रैली के दौरान जोरदार बम धमाका हुआ। जानकारी के मुताबिक, यह धमाका नवनिर्मित राजनीतिक दल 'नेशनल सिटिजन पार्टी' द्वारा आयोजित एक मार्च के दौरान हुआ। धमाके के वक्त रैली को एक महिला नेता संबोधित कर रही थीं, तभी अचानक जनता के बीच एक बम फटा, जिससे वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस घटना में कम से कम तीन लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं मिली है। घटना का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि मंच से भाषण जारी रहने के दौरान अचानक तेज आवाज के साथ धमाका होता है और धुआं उठने लगता है। धमाके के बाद रैली स्थल पर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए।

टीटीपी ने पाकिस्तान वायु सेना के ग्रुप कैप्टन की हत्या की जिम्मेदारी ली

इस्लामाबाद, एजेंसी। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानने रविवार दोपहर इस्लामाबाद में पाकिस्तान वायु सेना के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की हत्या की जिम्मेदारी ली है। गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान 22 वर्षीय साद अब्बासी के रूप में हुई है। टीटीपी ने सोशल मीडिया पर मोबाइल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज जारी किया। इसमें अधिकारी अपनी कार में सीट बेल्ट पहने दिख रहे हैं। यह फुटेज इस्लामाबाद पुलिस के उस दावे का खंडन करता है कि अधिकारी ने सड़क पर एक महिला को अपहरणकर्ता से बचाया था। टीटीपी ने कहा कि उसकी 'स्पेशल टारगेट किलर्स यूनिट' ने यह हत्या की। सूत्रों के अनुसार, तारिक खुफिया निदेशालय से जुड़े थे। इस निदेशालय ने हाल ही में अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के लिए निर्देशांक प्रदान किए थे, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं की मौत हुई थी। वह 'ऑपरेशन बुनियान-उम-मरसूस' में भी शामिल थे। यह ऑपरेशन पाकिस्तान ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जवाब में शुरू किया था। इस्लामाबाद पुलिस ने अब्बासी के खिलाफ हत्या और आतंकवाद के आरोप में मामला दर्ज किया।

गद्दाफी के देश में शांति लाएगा पाकिस्तान? 2 दुश्मनों की दोस्ती कराने में जुटे मुनीर

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान की कूटनीति को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने के बाद, अब पाकिस्तान युद्ध की आग में झुलस रहे लीबिया में भी 'शांति दूत' बनने की कोशिश कर रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने लीबिया के दो धुर विरोधी गुटों यानी पूर्वी और पश्चिमी सत्ता केंद्रों के बीच गुपचुप तरीके से मध्यस्थता शुरू कर दी है। हालांकि इसके पीछे पाकिस्तान का खुद का लालच छिपा है। यह लालच पैसों से जुड़ा है।

लीबिया के दोनों गुटों ने खुद की थी पाकिस्तान से अपील : साल 2011 में नाटो समर्थित विद्रोह के दौरान मुअम्मर गद्दाफी की सत्ता खत्म होने के बाद से ही लीबिया गृहयुद्ध का सामना कर रहा है। तब से यह देश पूर्वी और पश्चिमी प्रतिद्वंद्वी प्रशासनों में बंटा हुआ है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका यहां कूटनीतिक समाधान निकालने की कोशिश कर रहा था।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने मध्यस्थता की यह कोशिशें पिछले साल के अंत में शुरू की थीं। दिलचस्प बात यह है कि लीबिया के दोनों प्रतिद्वंद्वी पक्षों ने खुद इस्लामाबाद से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। अमेरिका 'पूरी तरह वाकिफ', सऊदी अरब का भी मिल रहा है बैकअप रॉयटर्स की रिपोर्ट में पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिका इस्लामाबाद की इस भूमिका से 'पूरी तरह वाकिफ' है और इसमें शामिल भी है। पाकिस्तान के इस प्रयास को सऊदी अरब का भी समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल ही इस्लामाबाद ने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया था। लीबिया में पाकिस्तान का यह कदम अमेरिका और ईरान के बीच हुई हालिया मध्यस्थता के ठीक बाद उठाया गया है। ईरान वाले मामले में भी पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए ट्रंप प्रशासन ने उसकी जमकर तारीफ की थी। पिछले महीने पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने रावलपिंडी में लीबिया के सैन्य प्रमुख सद्दाम हफ्तार से मुलाकात की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद हफ्तार ने वाशिंगटन का दौरा किया और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की थी। तब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर लीबियाई नेताओं के प्रयासों का स्वागत करते हुए लीबिया की एकता के लिए अमेरिकी समर्थन दोहराया था। मध्यस्थता के साथ-साथ पाकिस्तानी अधिकारी पूर्वी लीबिया स्थित सेना के साथ रक्षा संबंधों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इस रक्षा साझेदारी में पाकिस्तान द्वारा लीबिया को जे.एफ-17 लड़ाकू विमान बेचे जाने की संभावना भी शामिल है। यानी पाकिस्तान अपने चीन की मदद से बने जहाज बेंचकर लीबिया से पैसे कमाना चाहता है।

अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं : इस पूरे मामले में अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान अन्य क्षेत्रीय हितधारकों के साथ किस हद तक समन्वय कर रहा है। इस 'सीक्रेट' मध्यस्थता रिपोर्ट पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय, सेना की मीडिया विंग (ISPR), पश्चिमी और पूर्वी लीबियाई अधिकारियों के साथ-साथ कतर, तुर्किये, सऊदी अरब व अमेरिका के विदेश मंत्रालयों की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में ओमान तट के पास टैंकर पर हमला, लगी भीषण आग

मस्कट, एजेंसी। ओमान के तट के पास होर्मुज जलडमरूमध्य में मंगलवार सुबह एक टैंकर पर हमला हुआ। ब्रिटिश सेना ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मंगलवार तड़के ओमान के तट के पास होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिससे उसमें आग लग गई। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स सेंटर ने बताया कि टैंकर को जलडमरूमध्य में ओमान के लिमाह के पास निशाना बनाया गया।वहीं, ईरान के सरकारी टेलीविजन ने दावा किया है कि जहाज ने पहले जारी की गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की गई। फिलहाल जहाज की स्थिति, नुकसान या किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

सेंटर के मुताबिक, यह हमला तब हुआ जब टैंकर जलडमरूमध्य से दक्षिण की ओर गल्फ ऑफ ओमान की तरफ जा रहा था। प्रोजेक्टाइल जहाज के बाईं ओर (पोर्ट साइड) लगा। इस हमले से पर्यावरण पर कोई नुकसान नहीं हुआ है और अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी ने नहीं ली है, हालांकि हाल के दिनों में ओमान के पास के रास्ते से गुजरने वाले कम से कम दो अन्य जहाजों पर हुए हमलों के लिए ईरान पर शक जताया गया है। हालांकि, अमेरिका इस जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोलने के लिए ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ना चाहता है। अमेरिका का उद्देश्य ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम को वापस लेना और 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करना है। लेकिन पहले हुए ऐसे हमलों के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की थी, जिसके बाद ईरान ने खाड़ी के अरब देशों पर हमले किए। इससे तनाव बढ़ने का खतरा रहता है।

इस बीच, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिलहाल रुकी हुई है। यह बातचीत ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के दफन होने तक रुकी रहेगी। खामेनेई युद्ध की शुरुआत में मारे गए थे। उनके अंतिम संस्कार में शामिल लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मौत की सजा देने की मांग कर रहे हैं। अधिकारी खामेनेई के शव को रात में शिया मदरसा शहर कोम ले गए, जहां मंगलवार को उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

चीन में घूसखोर अफसर को मिली मौत की सजा, 30 साल में जुटाई थी अरबों की संपत्ति

बीजिंग, एजेंसी। चीन की एक अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में एक पूर्व स्थानीय अधिकारी को मौत की सजा सुनाई है। अधिकारियों के मुताबिक, उसने करीब 30 साल तक अपने पद का दुरुपयोग कर भारी मात्रा में रिश्वत ली। उन्होंने बताया कि दोषी अधिकारी ने रिश्वत के जरिए 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर या करीब 3 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाई थी। पूर्व अधिकारी की पहचान यांग यौलिन के रूप में हुई है जो चीन के पूर्वी तट पर स्थित जियांगसू प्रांत की राजधानी नानजिंग में आर्थिक विकास से जुड़ा था। चांगझोउ इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि यांग ने वर्ष 1993 से 2023 के बीच अवैध रूप से 2.21 अरब युआन (करीब 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 30 अरब रुपये) मूल्य की नकदी, संपत्ति और अन्य परिसंपत्तियां रिश्वत के रूप में स्वीकार कीं। कोर्ट के मुताबिक, यांग ने विभिन्न लोगों और कंपनियों से प्रोजेक्ट दिलाने, कारोबारी कामकाज में मदद करने, जमीन आवंटित कराने और फंड उपलब्ध कराने के बदले रिश्वत ली। कोर्ट ने यांग को केवल रिश्वतखोरी का ही नहीं, बल्कि गबन, रिश्वत देने, पद के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का भी दोषी ठहराया है। हाल के वर्षों में रिश्वत की रकम के लिहाज से इसे चीन के सबसे बड़े करप्शन केस में से एक माना जा रहा है। कोर्ट ने बताया कि सुनवाई के दौरान अपने अंतिम बयान में यांग ने अपने अपराध स्वीकार किए और अपने किए पर गहरा पछतावा और अपराधबोध व्यक्त किया। कोर्ट की ओर से जारी तस्वीरों में सफेद बालों वाले यांग गहरे रंग की जैकेट पहने हुए 2 वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के बीच खड़े दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस केस की सार्वजनिक सुनवाई मार्च और अप्रैल में 2 अलग-अलग दिनों में हुई थी। कोर्ट के मुताबिक, दोनों सुनवाई के दौरान 30 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यांग की व्यक्तिगत संपत्ति जब्त की जाएगी। साथ ही अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि रिश्वत के रूप में ली गई पूरी रकम की वसूली की जाए। यांग के खिलाफ कार्रवाई राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत हुई। यह अभियान पिछले एक दशक से जारी है।

ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस का नवीनीकरण अमेरिका के पुनरुत्थान को दर्शाता है

वॉशिंगटन, एजेंसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि व्हाइट हाउस का रेस्टोरेशन अमेरिका के बड़े रिन्यूअल का सिंबल है. उन्होंने कहा कि देश की सबसे जानी-मानी बिल्डिंग को देश की ताकत, इतिहास और कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए. रोज गार्डन में ट्रंप ने अपनी बातों का एक बड़ा हिस्सा व्हाइट हाउस के रेनोवेशन पर दिया. और इस काम को बचाने की कोशिश और देश के भविष्य के बारे में एक बयान, दोनों बताया. ट्रंप ने कहा, 'हम व्हाइट हाउस में बहुत सारा प्यार वापस डाल रहे हैं क्योंकि, सच कहूँ तो, इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था. राष्ट्रपति ने यह बताते हुए शुरुआत की कि रोज गार्डन में हाल ही में बड़े बदलाव क्यों हुए हैं, उन्होंने कहा कि साइट की दलदली जमीन के कारण असली लॉन काम का नहीं रहा. उन्होंने कहा, 'व्हाइट हाउस एक वेटलैंड पर बना था, और घास हमेशा बहुत गीली रहती थी,' और कहा कि विजिटर्स के जूते उसमें धंस जाते थे जिसे उन्होंने क्विकसैंड पिट बताया. उन्होंने कहा, 'नई ग्रेनाइट की सड़क को जमीन को बचाने के लिए डिजाइन किया गया था, साथ ही ऑफिशियल सेरेमनी के लिए जगह को ज़्यादा इस्तेमाल करने लायक बनाया गया था.' ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम को भी हाईलाइट किया. साथ ही वेस्ट विंग के रास्तों और व्हाइट हाउस के ऐतिहासिक कॉलम पर रेस्टोरेशन का काम भी किया गया. उन्होंने कहा कि वर्कर्स ने ओरिजिनल आर्किटेक्चरल डिटेल्स को ठीक करने के लिए एक सदी से ज़्यादा पुराना पेंट हटा दिया था. ट्रंप ने कहा, 'हमने कॉलम से लगभग 150 साल पुराना पेंट हटा दिया है. आप डिटेल्स भी नहीं देख सकते थे.' राष्ट्रपति ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ व्हाइट हाउस को मॉडर्न बनाना नहीं था, बल्कि अमेरिका के सबसे जरूरी नेशनल लैंडमार्क में से एक को बचाना भी था. उन्होंने कहा, 'यह हर 200 साल में होगा. आपको कोई न कोई ऐसा मिल जाएगा जो इसे वापस लाएगा ट्रंप ने बार-बार व्हाइट हाउस की तुलना विदेशों की ऐतिहासिक इमारतों से की, विंडसर कैसल और चीन के ग्रेट हॉल के दौरे को याद करते हुए. विंडसर कैसल के बारे में बात करते हुए उन्होंने किंग चार्ल्स III के साथ विलियम द कॉन्करर के साथ हुई बातचीत को याद किया. तभी मजाक में कहा कि शायद ब्रिटिश राजा को 'चार्ल्स द कॉन्करर' कहा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के पास दुनिया की दूसरी ताकतों के बराबर या उनसे बेहतर सेरेमोनियल सुविधाएं होनी चाहिए. ट्रंप ने कहा, 'मैं हाल ही में चीन के ग्रेट हॉल में था. उनके पास एक बहुत बड़ा बॉलरूम है. हम एक ऐसा बॉलरूम बनाने जा रहे हैं जो सबसे ऊपर होगा.' पूरे भाषण में ट्रंप ने व्हाइट हाउस को सिर्फ एक घर या काम की जगह से कहीं ज़्यादा बताया. 'प्रेसिडेंट ने नए जन्मे अमेरिकियों के लिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन के 'ट्रंप अकाउंट्स' प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए यह बात कही, लेकिन बार-बार उन इंस्टीट्यूशन को ठीक करने की थीम पर लौट आए। ट्रंप का लेटेस्ट रेनोवेशन प्रोग्राम जिसमें रोज गार्डन, ग्राउंड और एक प्रस्तावित नए बॉलरूम पर काम शामिल है।

मेलोनी पर ट्रंप के तंज को लेकर इटली ने दिखाया अमेरिकी राष्ट्रपति को आईना

रोम , एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। तुर्किये में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से ठीक पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मेलोनी का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्ट साझा किया। इसके जवाब में इटली ने कहा कि नेताओं के आने-जाने से देशों के रिश्ते नहीं बदलते। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर मेलोनी की एक संपादित तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'मुझसे दूरी बनाए रखने का आदेश (रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर) चाहिए।' यह पोस्ट ऐसे समय आई है, जब दोनों नेताओं की इस सप्ताह नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात होने की संभावना है।

इटली के नेताओं ने ट्रंप की टिप्पणी पर दिया क्या जवाब : ट्रंप की टिप्पणी पर इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेत्तो ने कहा कि इस पोस्ट पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उन्होंने कहा, 'सबसे अहम बात अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी देश के साथ रिश्ते बनाए रखना है। लोग आते-जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ते बने रहते हैं। इटली के विदेश मंत्री अंतोनियो तायानी ने भी विवाद को ज्यादा तूल नहीं दिया। उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों देशों के संबंध किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी से कहीं बड़े हैं।' हालांकि, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप की ताजा टिप्पणी पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

जी-7 सम्मेलन के बाद शुरू हुई थी तल्खी : दोनों नेताओं के बीच तनाव की शुरुआत हाल ही में हुए जी-7 शिखर सम्मेलन के बाद हुई थी। पिछले महीने ट्रंप ने दावा किया था कि सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने उनसे कई बार तस्वीर खिंचवाने का अनुरोध किया था और उन्होंने सिर्फ इसलिए इसकी अनुमति दी क्योंकि उन्हें 'उन पर तरस आ गया था।' ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया था कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करने के बाद मेलोनी घरेलू राजनीतिक कारणों से अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही हैं। मेलोनी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था, 'ये लगातार और बिना किसी वजह के किए जा रहे हमले पूरी तरह निरर्थक हैं।' उन्होंने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा था, 'आपकी दोस्त होने से मेरी लोकप्रियता नहीं बढ़ी है। मेरा सुझाव है कि आप अपनी लोकप्रियता पर ध्यान दें।' एक अन्य साक्षात्कार में मेलोनी ने कहा था, 'इटली और मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। मैं अमेरिका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मजबूत रिश्ते स्पष्ट बातचीत पर भी टिके होते हैं और मैं साफ बात करने वाली व्यक्ति हूं।' ट्रंप और मेलोनी को लंबे समय तक समान विचारधारा वाला सहयोगी माना जाता रहा है। अवैध प्रवासन, रूढ़िवादी राजनीति और पश्चिमी देशों की सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर दोनों की सोच मिलती रही है।

चीन में कुदरत का कहर: हुबेई में तूफान और बिजली गिरने से 8 की मौत, अब सुपर टाइफून 'बावी' का खतरा

बीजिंग, एजेंसी। चीन के मध्य हिस्से में स्थित हुबेई प्रांत में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। सोमवार शाम को आए विनाशकारी आंधी-तूफान और गरज के साथ हुई भारी बारिश ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय प्रशासन और सरकारी मीडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। हुबेई के आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने जानकारी दी है कि यह तूफान इतना शक्तिशाली था कि इसने कुछ ही घंटों में पूरे क्षेत्र के जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया।

कई शहरों में 149 किमी/घंटा की रफ्तार से चली हवाएं : शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार शाम को महज चार घंटों के भीतर हुबेई के कई प्रमुख शहरों में 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चलीं। इन तेज हवाओं ने हुआंग्शी, हुआंगगांग , एझोउ और जियानिंग जैसे शहरों में भीषण नुकसान पहुंचाया है। सड़कों पर सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, बिजली के बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची और कई घरों की छतें उड़ गईं, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी हैं, लेकिन खराब मौसम बाधा बना हुआ है। चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि खतरा अभी टला नहीं है और आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, देश के उन विभिन्न हिस्सों में जहां लगभग 20 करोड़ लोग निवास करते हैं, वहां मूसलाधार बारिश और बवंडर आने की संभावना बनी हुई है। वहीं, दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र के गुआंग्शी और पूर्वी प्रांतों जियांग्सू और शेडोंग में अगले 24 घंटों के भीतर 260 मिमी तक की अत्यधिक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। यह भारी बारिश न केवल शहरी इलाकों में बाढ़ ला सकती है, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में खतरनाक भूस्खलन भी हो सकता है। एक तरफ जहां चीन की मुख्य भूमि तूफानों से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत महासागर में उठा सुपर टाइफून 'बावी' ताइवान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार, यह चक्रवात 180 मील प्रति घंटे की प्रचंड और विनाशकारी रफ्तार वाली हवाओं के साथ आगे बढ़ रहा है।

2,000 साल पहले थाईलैंड गए थे भारत के व्यापारी, खुदाई में मिले बहुत बड़े सबूत

बैंकॉक, एजेंसी। आज भारतीयों के बीच एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना थाईलैंड हजारों साल पहले भी भारत से जुड़ा हुआ था। हाल ही में एक खोज ने यह बात साबित कर दी है। दरअसल थाईलैंड में बीते दिनों इतिहासकारों को एक ऐतिहासिक कामयाबी मिली। यहां पश्चिमी थाईलैंड में चल रही खुदाई के दौरान करीब 2,000 साल पुरानी 2 सोने की अंगूठियां मिली हैं। इन अंगूठियों का संबंध भारत से बताया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक अंगूठी पर प्राचीन भारतीय 'ब्राह्मी' लिपि में कुछ लिखा हुआ है। अब वैज्ञानिक इसे दो हजार साल पहले भारत और थाईलैंड के बीच मजबूत व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का जीता-जागता सबूत बता रहे हैं।

थाईलैंड के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, ये अंगूठियां पिछले हफ्ते पेत्चाबुरी प्रांत के दोन याई थोंग साइट पर मिली हैं। वैज्ञानिक यहां मानव कंकालों की खुदाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञों ने जब इन अंगूठियों की शुरुआती जांच की, तो एक के बाद एक इतिहास के कई पन्ने खुलते चले गए।

अंगूठियों पर क्या लिखा है : एक अंगूठी पर ब्राह्मी लिपि में लिखे अक्षरों को डिकोड किया गया तो उस पर 'पुस रखितस' लिखा हुआ मिला। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका अर्थ होता है, 'वह व्यक्ति जिसे पुष्य का संरक्षण प्राप्त है।' बता दें कि भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान में पुष्य को सबसे शुभ और कल्याणकारी नक्षत्र माना जाता है। वहीं एक अन्य अंगूठी भी मिली है। इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ये दोनों अंगूठियां प्राचीन भारतीय जाति व्यवस्था के 'वैश्य' समुदाय के किसी अमीर व्यापारी की रही होंगी, जो उस दौर में व्यापार के सिलसिले में थाईलैंड आया होगा।

पुरातत्व विभाग के हाथ लगा खजाना : थाईलैंड में यह खुदाई आखिर शुरू क्यों हुई? रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंकॉक से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित इस साइट की खोज इस साल की शुरुआत में ही हुई। यहां स्थानीय ग्रामीणों को एक धान के खेत में प्राचीन चीजें मिलीं। इसके बाद सरकार ने बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू करवाई। फरवरी से अब तक यहां 8 मानव कंकाल, कांसे और सोने के गहने और प्राचीन मिट्टी के बर्तन मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों ने इस साइट को थाईलैंड के आयरन एज के समय का यानी आज से 1,500 से 2,500 साल पुराना बताया है। अगले महीने खुदाई पूरी होने के बाद इन्हें आम जनता के प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा।

राखीगढ़ी के राज भी खुलेंगे : थाईलैंड में मिली बड़ी कामयाबी के बीच भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर एक बड़ी हलचल हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हरियाणा के ऐतिहासिक स्थल राखीगढ़ी से खुदाई में मिले मानव कंकालों को वैज्ञानिक और डीएनए विश्लेषण के लिए भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (को सौंप दिया है। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक दोनों संस्थानों के बीच हुए एक नए समझौते के तहत अब राखीगढ़ी के कंकालों पर अत्याधुनिक मल्टी-डिसिप्लिनरी रिसर्च होगी। गौरतलब है कि राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है। यहां का ड्रेनेज सिस्टम, बेहतरीन टाउन प्लानिंग और अब इन कंकालों के वैज्ञानिक टेस्ट से प्राचीन भारतीयों के रहन-सहन और उनके जेनेटिक्स को लेकर कई बड़े और खुलासे होने की उम्मीद है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बारुईपुर में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी प्रभाव मुठभेड़ में ढेर

कोलकाता (एजेंसी)। बंगाल के बारुईपुर दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपी प्रभास मंडल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बंगाल पुलिस ने सोमवार आरोपी को गिरफ्तार किया था। बारुईपुर एसपी के मुताबिक आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। क्राइम सीन को फिर से बनाने में, उसने पुलिस से हथियार छीनने और उन पर गोली चलाने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जो प्रभास को लगी अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बारुईपुर में लड़की के दुष्कर्म और हत्या के बाद सरकार और पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। 11 साल की नाबालिग की हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने घटना की हैवानियत की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के शरीर पर गंभीर चोट, यौन उत्पीड़न और शारीरिक यातनाओं के स्पष्ट संकेत मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया। इसके बाद उसे बोरी में भरकर तालाब में फेंक दिया। रिपोर्ट में उल्लेख है कि तालाब में फेंके जाने के समय वह जीवित थी। सिर पर गहरे घाव, शरीर पर खरोंच और काटने के निशान मिले हैं। गुप्तांगों पर भी गंभीर चोटों के निशान मिले। पानी शरीर के भीतर जाने से फेफड़ों और पेट में सूजन आ गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक घटना बारुईपुर थाना क्षेत्र के धपधपी-2 पंचायत के सूर्यपुर हाट की है। पीड़िता शनिवार शाम घर से खाने का सामान लेने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। रविवार सुबह घर के पास एक तालाब से उसका शव मिला। उसी रात सीसीटीवी फुटेज में चार लोग नाबालिग को अपने साथ ले जाते दिखे। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है।

स्कूल बस इंतजार कर रहे थे बच्चों को कार सीख रही महिला ने मारी टक्कर

नई दिल्ली (एजेंसी)। यूपी के ग्रेटर नोएडा के पंचशील ग्रीन्स-2 सोसायटी के बाहर बुधवार सुबह कार चलाना सीख रही एक महिला की गाड़ी अनियंत्रित होकर स्कूल बस का इंतजार कर रहे बच्चों पर चढ़ गई जिससे पांच बच्चे को मामूली चोटें आईं हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। घटना उस वक्त हुई जब सोसायटी में रहने वाले कुछ बच्चे स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे तभी एक महिला कार लेकर वहां से गुजरी। पुलिस के मुताबिक महिला अभी कार चलाना सीख ही रही थी और उसे गाड़ी चलाने का ज्यादा अनुभव भी नहीं था। इसी दौरान उसका कार से नियंत्रण छूट गया और गाड़ी सीधे बच्चों से टकरा गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और कार्रवाई शुरू की। फिलहाल यह साफ नहीं हुआ है कि महिला के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं, लेकिन पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है ताकि पूरी घटना का सही कारण सामने आ सके।

जमीन विवाद में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपियों को तलाश रही पुलिस

आरा (एजेंसी)। भोजपुर जिले के बड़की खड़ाव गांव में बुधवार सुबह जमीन विवाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान बड़की खड़ाव गांव निवासी बीरेन्द्र कुमार सिंह (34) के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि घर के बगल की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बुधवार सुबह इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक आरोप है कि दूसरे पक्ष के व्यक्ति ने विक्रांत कुमार सिंह पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। हमलावर ने उनके सिर और दाहिनी ओर सीने के पास चाकू मारा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है।

गर्भवती आईपीएस अधिकारियों के प्रशिक्षण पर रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक अहम कानूनी लड़ाई में, एक गर्भवती महिला आईपीएस अधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान गर्भवती होने पर रोक लगाने वाले करीब तीन दशक पुराने सरकारी नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इसतरह के फैसले पुराने नियमों के बजाय आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर होने चाहिए। मध्य प्रदेश कैडर की 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी उर्वशी सेंगर ने याचिका दायर की है। सेंगर ने नवंबर 2023 में अपना फेज-1 प्रशिक्षण शुरू किया था। अप्रैल 2025 में फेज-2 के दौरान जब वे गर्भवती हुईं, तब उन्हें प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ने और प्रसव के एक साल बाद अगली बैच के साथ दुबारा प्रशिक्षण लेने के लिए कहा गया। सितंबर 2025 में बच्चे के जन्म के बाद उन्होंने मेडिकल फिटनेस के आधार पर फेज-2 प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति मांगी, लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने 1993 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) का हवाला देकर उनकी मांग ठुकरा दी। यह ज्ञापन कहता है कि गर्भवती आईपीएस प्रोबेशनर को तुरंत प्रशिक्षण से रोक दिया जाएगा और वे प्रसव के एक साल बाद ही फिर प्रशिक्षण शुरू कर सकेंगी। आईपीएस महिला अधिकारी सेंगर ने पहले केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (सीएटी) का रुख किया, जिसने उन्हें अंतरिम आदेश में आवश्यक मेडिकल औपचारिकताएं पूरी करने पर प्रशिक्षण जारी रखने की अनुमति दे दी थी। हालांकि, पुलिस अकादमी ने आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने 22 जून को सीएटी के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह नियम महिला अधिकारी और उसके बच्चे दोनों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दायर याचिका में कहा गया है कि 1993 का यह नियम बिना किसी भेदभाव के सभी गर्भवती अधिकारियों पर समान रूप से लागू होता है, जबकि फेज-2 प्रशिक्षण मुख्य रूप से कक्षा-आधारित और अकादमिक होता है, जो शारीरिक रूप से अत्यधिक कठिन नहीं होता। याचिका में उजागर किया गया है कि 2004 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने आईएएस महिला अधिकारियों के लिए इसी तरह के नियम में संशोधन किया था, जिससे उन्हें मेडिकल फिटनेस के आधार पर प्रशिक्षण पूरा करने की अनुमति मिली थी।

कांग्रेस ने भाजपा-संघ पर लगाया मिलीभगत का आरोप, ट्रस्ट भंग करने की मांग

अयोध्या (एजेंसी)। कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्य विपक्षी दल ने दावा किया कि ये संगठन असली दोषियों को बचाने के लिए पूरे प्रकरण पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि वर्तमान राम मंदिर ट्रस्ट को तुरंत भंग कर दिया जाए और नए ट्रस्ट में संघ परिवार या विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के प्रतिनिधियों के बजाय हिंदू संतों और धार्मिक प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, ताकि मंदिर की पारदर्शिता और आस्था की शुचिता बनी रहे।

यह राजनीतिक घमासान उस समय और तेज हो गया जब राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने एक हस्तलिखित संदेश में खुद पर लगे गबन के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वे विशेष जांच दल (एसआईटी) की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही जवाब देंगे। गौरतलब है कि इससे ठीक एक दिन पहले ट्रस्ट ने चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए थे। दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की कि इस मामले की स्वतंत्र जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हो और मंदिर के चढ़ावे का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ने की मांग करते हुए कहा कि चूंकि मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा का नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था, इसलिए इस मामले पर उनकी जिम्मेदारी बनती है। गहलोत ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल (2018-23) का जिक्र करते हुए एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से जो पत्थर लाया जा रहा था, वहाँ बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा था। उन्होंने चंपत राय से खुद कहा था कि पवित्र कार्य में अवैध पत्थरों का उपयोग न हो। बाद में राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र के सहयोग से उस क्षेत्र को वन भूमि की श्रेणी से हटाया गया ताकि काम न रुके। गहलोत ने कहा कि इस पूरे प्रकरण से भाजपा और संघ परिवार का वास्तविक चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया है और इन संगठनों ने मंदिर प्रशासन पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी गहलोत ने तीखा पलटवार किया, जिसमें योगी ने कहा था कि कांग्रेस को इस पर बोलने का अधिकार नहीं है। गहलोत ने कहा कि अगर ऐसा है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद नए ट्रस्ट का नेतृत्व क्यों नहीं करते और जनता का विश्वास बहाल क्यों नहीं करते? यह बयानबाजी दर्शाती है कि राम मंदिर से जुड़ा यह विवाद अब एक गंभीर राजनीतिक रूप ले चुका है।

मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा, एक ही रनवे पर आमने-सामने आए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार रात एक बड़ा विमान हादसा टल गया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के दो विमान एक ही रनवे पर आमने-सामने आ गए, जिससे यात्रियों के बीच कुछ समय के लिए घबराहट और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) की सतर्कता और समय रहते उठाए गए कदमों से संभावित बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे की है। उस समय बागडोगरा से मुंबई पहुंचा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के बाद अभी पूरी तरह रनवे से बाहर नहीं निकला था। इसी दौरान मुंबई से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट ॡ816 को उसी रनवे से उड़ान भरनी थी। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि विमान ने टेकऑफ की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन इसी बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोल से तुरंत उड़ान रोकने का निर्देश मिला। निर्देश मिलते ही पायलट ने टेकऑफ रन को तत्काल रद्द कर दिया और विमान को सुरक्षित रूप से वापस पार्किंग बे में ले जाया गया। इस त्वरित कार्रवाई से एक संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई। एयरलाइन के अनुसार, टेकऑफ रन रद्द किए जाने के बाद विमान की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के तहत आवश्यक तकनीकी जांच की जाएगी। इसके बाद ही विमान को दोबारा उड़ान के लिए मंजूरी दी जाएगी। साथ ही यात्रियों को उनके गंतव्य तक जल्द पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। एयर इंडिया ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि एटीसी के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। हालांकि, एयरलाइन ने घटना के तकनीकी कारणों या दोनों विमानों में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है।

अमरनाथ यात्रा: रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु उमड़े, 6 जत्थे में 8 हजार से अधिक रवाना

जम्मू (एजेंसी)। पवित्र अमरनाथ यात्रा लगातार नए कीर्तिमान बना रही है। मंगलवार को यात्रा के छठे जत्थे में अब तक की सबसे बड़ी संख्या में 8,815 श्रद्धालु कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुए। इन श्रद्धालुओं को बालटाल और पहलगाम के आधार शिविरों तक पहुंचाने के लिए कुल 363 वाहनों का एक विशाल काफिला तैनात हुआ। जिला प्रशासन अधिकारियों ने बताया कि यात्रा के पहले चार दिनों में ही 86 हजार से अधिक श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जिससे इस वर्ष यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है।

6 जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं में 5,831 पुरुष, 2,193 महिलाएं, 30 बच्चे, 598 साधु, 131 साध्वियां, एक बाल साधु तथा 31 विदेशी पुरुष श्रद्धालु शामिल रहे, जो यात्रा की व्यापक पहुंच को दिखाता है। बालटाल मार्ग के लिए 3,989 श्रद्धालु सुबह 3.35 बजे 181 वाहनों में रवाना हुए, जबकि पारंपरिक पहलगाम मार्ग के लिए 4,826 श्रद्धालु सुबह 4.08 बजे 182 वाहनों के काफिले के साथ निकले। इस काफिले में 172 बसें, 58 मीडियम मोटर व्हीकल, 130 लाइट मोटर व्हीकल और तीन दोपहिया वाहन शामिल थे।

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पूरे मार्ग पर सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाएं, यातायात प्रबंधन और अन्य आवश्यक सेवाओं की मुस्तैद व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा का सामना न करना पड़े।

गौरतलब है कि 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा का शुभारंभ 3 जुलाई को हुआ था और इसका समापन 28 अगस्त को होगा। दक्षिण कश्मीर हिमालय में समुद्र तल से लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु हर वर्ष पहुंचते हैं। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या इस यात्रा की लोकप्रियता और धार्मिक आस्था की गहराई का स्पष्ट प्रमाण है। श्रद्धालुओं में बढ़ता जोश व उत्साह इतना है कि रिकॉर्ड संख्या में लोग बिना पंजीकरण के भी पहुंच रहे हैं और मौके पर ही तत्काल पंजीकरण करा रहे हैं।

भारी बारिश में मुंबई का हाल बेहाल, सड़कों पर भरा पानी, रेल यातायात भी ठप

-जलभराव के चलते रिहायशी इलाके में आया 6 फीट मगरमच्छ, रेस्क्यू कर पकड़ा

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन बुरा असर पड़ा है। पानी भरने से जहां एक तरफ रेल यातायात ठप है, वहीं दूसरी तरफ जलभराव के कारण जंगली जानवर भी रिहायशी इलाकों में घुस आए हैं। ऐसा ही घटना पवई के चांद शाह वली दरगाह के पास देखने को मिली। जहां खड़ी गाड़ियों के नीचे एक 6 फीट लंबा मगरमच्छ देखा गया। भारी बारिश के कारण मगरमच्छ रास्ता भटक कर झील से बाहर आ गया था।

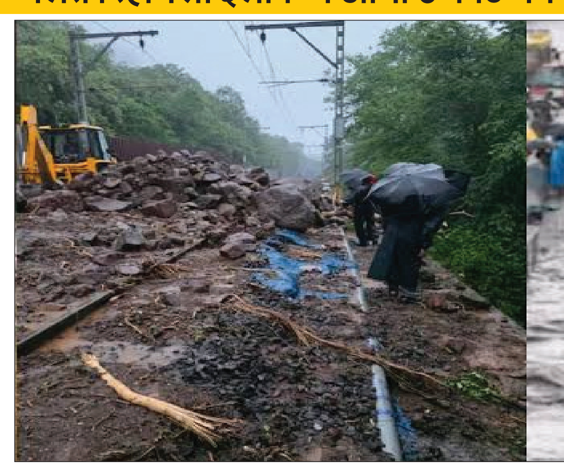

सूचना मिलते ही वन विभाग और वन्यजीव संस्थाओं की टीम ने मिलकर सुरक्षित रूप से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। डॉक्टर द्वारा जांच किए जाने के बाद इसे वापस इसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पर्यावरणविदों का कहना है कि झीलों के आस-पास बढ़ते निर्माण कार्यों की वजह से मगरमच्छों के रहने की जगह कम हो रही है, जिससे वे इंसानी बस्तियों की तरफ आ रहे हैं।

बता दें मुंबई में भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर वेस्टर्न रेलवे पर पड़ा है। नवसारी-मारोली सेक्शन में पटरियों पर पानी भर जाने के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बुधवार को चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिनमें अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस, अहमदाबाद-बांद्रा टर्मिनस कर्णावती एक्सप्रेस, अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल एसी डबल डेकर एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले हेल्पलाइन नंबर 139 या ऐप के जरिए अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। मौसम विभाग ने बुधवार को मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग की माने तो निचले इलाकों में बाढ़, जलभराव, भूस्खलन और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग के मुताबिक 9 जुलाई से बारिश की रफ्तार थोड़ी कम होगी और 12 जुलाई से हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है।

बता दें एक तरफ जहां मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है, वहीं राज्य के कुछ हिस्सों जैसे धुले, नंदुरबार, सोलापूर और मराठवाड़ा में अब तक औसत से कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय और कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम को देखकर ही खेती की तैयारी करें और जहां कम बारिश हुई है, वहां जमीन में अच्छी नमी होने से पहले बुवाई की जल्दबाजी न करें।

महिलाओं को दिल्ली सरकार देगी तोहफा ! हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए

-महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ 28 अगस्त को कर सकते हैं पीएम मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए बहुप्रतीक्षित महिला समृद्धि योजना का औपचारिक शुभारंभ 28 अगस्त को किया जा सकता है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी योजना की शुरुआत कर सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है।

दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल तैयार है और पात्रता के मानदंड भी तय कर दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमान है कि दिल्ली की 20 से 22 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता पहले कह चुकी हैं कि सरकार योजना को पूरी तैयारी के साथ लागू करना चाहती है, ताकि सभी पात्र महिलाओं तक इसका लाभ बिना किसी बाधा के पहुंचे और भविष्य में भी योजना सुचारु रूप से चलती रहे।

महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए तय प्रमुख पात्रताएं इस प्रकार हैं। आवेदक महिला की आयु 21 से 60 साल के बीच हो। परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से 3 लाख तक हो। दिल्ली की स्थायी निवासी होना जरुरत है। राशन कार्ड धारक महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने कुछ श्रेणियों की महिलाओं को योजना से बाहर रखा है। इनमें सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं, आयकर भरने वाली महिलाएं, सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं और चार पहिया वाहन की मालिक महिलाएं शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। आवेदन के समय महिलाओं को जो जानकारी देनी होगी उसमें आधार नंबर, नाम और जन्म तिथि, लिंग पिता या माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, दिल्ली में निवास की अवधि आधार से लिंक बैंक खाता। महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

मुस्लिम आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची विजय सरकार, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

नई दिल्ली (एजेंसी)। इस्लाम धर्म अपनाने वालों को आरक्षित वर्ग के तहत प्राप्त आरक्षण के लाभ को खत्म करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि इस्लाम धर्म अपना लेने वाला व्यक्ति पिछड़े वर्ग के तहत मिलने वाले आरक्षण के लाभ का हकदार नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने इसको लेकर तमिलनाडु सरकार के 2024 के आदेश को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था। गो-हत्या पर रोक हटाने की मांग के बाद तमिलनाडु सरकार ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में तमिलनाडु सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अधिसूचित समुदाय या अनुसूचित जाति से इस्लाम धर्म अपनाने वाले लोगों को पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) मानने का आदेश जारी किया था। यही नहीं, तत्कालीन स्टालिन सरकार ने कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी जारी करना शुरू कर दिया था, जिन मुस्लिम जातियों को यह आरक्षण दिया जा रहा था उनमें- अंसार, दक्कनी मुस्लिम, दुबेकुला, लब्बाइस, रोवथर, मराकायार, मपिल्ला, शेख और सैयद शामिल हैं।

मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस पीबी बालाजी की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी आदेश उन न्यायिक निर्णयों के पूरी तरह से खिलाफ हैं, जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इन न्यायिक फैसलों के मुताबिक धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को सिर्फ मुसलमान ही माना जा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तमिलनाडु की टीवीके सरकार ने इस मामले में 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया है।

तीन देशों के दौरे में पीएम मोदी ब्रह्मोस, रेयर अर्थ मैटेरियल और समुद्री सीमा पर कर रहे चर्चा

-इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और अस्त्र देगा भारत, चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगेगा ब्रेक

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे में जिन समझौतों और साझेदारियों पर चर्चा हो रही है, उनका असर सीधे तौर पर चीन की रणनीतिक क्षमता पर पड़ सकता है। पीएम मोदी की ये यात्राएं दक्षिण चीन सागर में शक्ति के संतुलन पर असल डालने वाली हैं। भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और अस्त्र देकर चीन की दादागिरी पर एक ब्रेक सा लगा दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में चीन ने इंडो पैसिफिक और दक्षिण चीन सागर के कई देशों पर धौंस जमाने की कोशिश की। एक ऐसी रणनीति पर काम किया, जिससे वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों पर सीधा दबाव बढ़ा और तो और चीन ने दक्षिण चीन सागर के साथ भारत की घेराबंदी के लिए इंडिया के पड़ोसी देशों को साधने की कोशिश की। अब भारत के सहयोग से इंडोनेशिया ने तय किया है कि वह अपनी सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा मजबूत करेगा और इसीलिए उसने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। इससे अब इंडोनेशिया की समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ेगी।

ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से दुश्मन के जहाजों, समुद्री ठिकानों और जमीन पर मौजूद सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इंडोनेशिया की बढ़ती ताकत को देख चीन का परेशान होना लाजिमी है। ब्रह्मोस डील के अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच सबांग पोर्ट को लेकर बढ़ता सहयोग सबसे ज्यादा चर्चा में है। सबांग बंदरगाह मलक्का जलडमरूमध्य के मुहाने पर स्थित है, जहां से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। चीन का करीब 80 फीसदी ऊर्जा आयात इसी रास्ते से होकर आता है। ऐसे में भारत की बढ़ती मौजूदगी चीन का टेंशन और बढ़ा सकती है। इंडोनेशिया के बाद पीएम मोदी 8 जुलाई को मेलबर्न पहुंच रहे हैं, जहां उनका ऑस्ट्रेलिया दौरा 8-10 जुलाई तक चलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ सालों में रणनीतिक साझेदार के रूप में तेजी से करीब आए हैं। दोनों देश क्वाड समूह का हिस्सा हैं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त एवं खुले समुद्री मार्गों की वकालत करते हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा में महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और रक्षा सहयोग पर चर्चा केंद्र में है। चीन लंबे समय से दुर्लभ खनिजों और इसके वैश्विक सप्लाई चेन पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस बार रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स सहयोग पीएम मोदी की यात्रा का सबसे अहम एजेंडा माना जा रहा है। दोनों देश ऐसे समझौतों पर काम कर रहे हैं, जिनसे भारत की चीन पर निर्भरता कम हो और इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और रक्षा उद्योग के लिए जरूरी खनिजों की सुरक्षित सप्लाई सुनिश्चित हो सके।

ऑस्ट्रेलिया के बाद पीएम मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। न्यूजीलैंड भले ही सैन्य दृष्टि से बड़ा खिलाड़ी न हो, लेकिन अपने लोकेशन की वजह से हिंद-प्रशांत की राजनीति में उसका महत्व बढ़ रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग पर जोर दिया जा रहा है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी चर्चा तेज हुई है, लेकिन इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। चीन लंबे समय से न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, लेकिन

वेलिंगटन अब अपने आर्थिक विकल्पों को विविध बनाने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि अपनी न्यूजीलैंड यात्रा में वे आर्थिक, व्यापारिक और कमर्शियल संबंधों को और कैसे बेहतर बनाया जाए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।